राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

रायपुर एवं दुर्ग से प्रकाशित

समय दर्शन

ESTD : Since 2011

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर

निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

वर्ष 07, अंक 138 पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रूपये | रायपुर, गुरुवार 17 जुलाई 2025 | www.samaydarshan.in

विधानसभा का मानसून सत्र

डॉ. महंत ने कहा- पीएम आवास के नाम पर अधिकारी-कर्मचारी ले रहे पैसा

उप मुख्यमंत्री बोले- सुशासन है और सुदर्शन भी, कोई नहीं बचेगा...

रायपुर (समय दर्शन)। रायपुर। विधानसभा में आज प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बीच तीखे सवाल-जवाब हुए। डॉ. महंत ने आरोप लगाया कि पीएम आवास के नाम पर अधिकारी कर्मचारी पैसे ले रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां सुशासन है और सुदर्शन भी, गलत दिखेगा तो बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं बचेगा।

प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत का सवाल था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जून 2025 तक की स्थिति में कितने कितने हितग्राहियों को पहली, दूसरी तथा तीसरी किस्त की राशि जारी की गई? निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सके आवासों के पीछे क्या कारण हैं? इस योजना से संबंधित कितनी शिकायतें सुशासन तिहार में प्राप्त हुई? कितनों का निराकरण किया गया? कितनी लंबित हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मनरेगा योजना से कितने दिनों का, किस दर पर, कितनी मजदूरी देने का प्रावधान है? क्या इसका पालन किया जा रहा है?

उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) विजय शर्मा की ओर से जवाब आया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) हेतु राज्य को 34 हजार 396 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिलों व्दारा सर्वेक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों के आवास स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित सुशासन तिहार में कुल 2 हजार 965 शिकायतें प्राप्त हुईं, समस्त शिकायतों का निराकरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में महात्मा गांधी नरेगा से 90 दिनों की मजदूरी देने का प्रावधान है।

भारत सरकार व्दारा राज्य हेतु वर्तमान में प्रति दिन मजदूरी की दर 261 रुपये का निर्धारण किया गया है, जिसका पालन किया जा रहा है।

डॉ. महंत ने पूछा कि पीएम आवास ग्रामीण योजना में आवास कब पूर्ण माना जाता है? उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 किश्तों में राशि दी जाती है। नरेगा के तहत 90 दिनों की राशि का भुगतान होता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण होने पर दूसरी किश्त दी जाती है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर तीसरी किश्त दी जाती है। डॉ. महंत ने पूछा कि पीएम आवास में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15 प्रतिशत एवं दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत का कोटा रखा गया है। क्या इसका पालन हो रहा है? उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे सूची के अनुरुप काम हो रहा है। डॉ. महंत ने कहा कि जैसा कि पुलिस वाले किसी की सुनते नहीं, कुछ इसी तरह का यहां भी हो रहा है। कोटे वाले नियम का पालन नहीं हो रहा है। यह बात छुपाई जा रही है। इसकी ऊपर तक शिकायत कर सकता हूं। पीएम आवास के नाम पर अधिकारी कर्मचारी पैसे ले रहे हैं। 2 हजार 965 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तखतपुर समेत कई स्थानों से इस तरह की शिकायतें आई हैं। मंत्री ने कहा कि यहां सुसाशन है और सुदर्शन भी, गलत दिखेगा तो बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं बचेगा। डॉ. महंत ने कहा कि आप ही के कबीरधाम क्षेत्र में पीएम आवास के नाम पर बैगा आदिवासियों से अवैध वसूली की जानकारी मिली है। तखतपुर में पंचायत के माध्यम से शिकायत हुई है। ऐसी शिकायतें हर जगह से हैं। क्या किसी कलेक्टर को सस्पेंड करेंगे? मंत्री ने कहा कि कवर्धा की जांच चल रही है। तखतपुर की भी जांच करा लेंगे। डॉ. महंत ने कहा ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां मनरेगा की शत प्रतिशत राशि नहीं दी जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री का जशपुर जिला भी शामिल है। बीजापुर में तो 38 प्रतिशत ही राशि दी गई। मंत्री ने कहा कि बीजापुर को विशेष तौर पर दिखवा लेंगे। बाकी 30 जून तक सभी जगह लेबर पेमेंट हो चुका है। इसके बाद डॉ. महंत कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर गए जिससे उप मुख्यमंत्री उत्तेजित हो गए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों की सरकार थी तो गरीबों की आवास योजना को ठुकराकर छत्तीसगढ़ के लोगों को अपमानित किया गया था। केन्द्र सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर जो पत्र भेजा था उसे आप लोगों ने वापस कर दिया था। हमारी सरकार आई तो 100 प्रतिशत आवास स्वीकृत किया गया। 41 लाख नये आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई। उप मुख्यमंत्री की इस बात के विरोध में विपक्षी विधायक कुछ देर तक शोर मचाते रहे।

AM/NS इंडिया ने चित्रकोंडा में शुरू की 'बेटी पढ़ाओ स्कॉलरशिप', 18 छात्राओं को मिली 3.09 लाख की सहायता

दंतेवाड़ा (समय दर्शन)। चित्रकोंडा, मलकानगिरी (ओडिशा), आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS इंडिया) ने अपने प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रम 'बेटी पढ़ाओ स्कॉलरशिप' को ओडिशा के मलकानगिरी जिले के चित्रकोंडा में विस्तारित किया है। इस पहल का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने शैक्षणिक सपनों को पूरा कर सकें।

मार्च 2022 में शुरू हुई यह स्कॉलरशिप योजना छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हजारों छात्राओं के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर चुकी है। चित्रकोंडा में इसकी शुरुआत के साथ AM/NS इंडिया ने नारी सशक्तिकरण और शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। इस अवसर पर जिले की 18 मेधावी छात्राओं को कुल 3.09 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

कार्यक्रम में छात्राओं, उनके अभिभावकों और स्कूल शिक्षकों के साथ-साथ प्रमुख अतिथि के रूप में तहसीलदार नटबरा गरदा, BDO प्रीता कुमार, जिला परिषद सदस्य सुश्री बिनती खिल्ला, AM/NS चित्रकोंडा के प्लांट इंचार्ज श्री प्रवीण पी., और बड़ापदर, डोरागुड़ा, गुन्टावाड़ा व नुआगुड़ा के सरपंच उपस्थित रहे।

छात्रा हीरामनी सिसा ने कहा, यह स्कॉलरशिप मेरे लिए वरदान है। उच्च शिक्षा के खर्चों के कारण मैंने एक साल रुकने का सोचा था, लेकिन अब यह सहायता मेरे सपनों को साकार करने में मदद करेगी। मैं ,स्नहस इंडिया की आभारी हूं।

तहसीलदार नटबरा गरदा ने इस पहल को सराहते हुए कहा, यह स्कॉलरशिप आर्थिक तंगी और शिक्षण संस्थानों की दूरी के कारण पढ़ाई से वंचित बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

BDO सुश्री प्रीता कुमार ने AM/NS इंडिया की इस पहल को समाज को सशक्त बनाने वाला कदम बताया, जबकि जिला परिषद सदस्य सुश्री बिनती खिल्ला ने कहा, शिक्षा ही प्रगति का रास्ता है। बेटियों को किसी भी हाल में पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए।

गुन्टावाड़ा के सरपंच श्री त्रिनाथ किरसानी ने इसे प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह न केवल छात्राओं, बल्कि उनके अभिभावकों को भी प्रोत्साहित करेगा।

कार्यक्रम में छात्राओं के साथ उनके माता-पिता को भी सम्मानित किया गया, जो बेटियों की शिक्षा में उनके योगदान को दर्शाता है। AM/NS इंडिया की यह पहल चित्रकोंडा में शिक्षा के प्रति âpositive सोच को बढ़ावा देगी और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा मण्डल के प्रतिनिधिमंडल ने एनएमडीसी, किरंदुल के अधिशासी निदेशक से की सौजन्य मुलाकात

दंतेवाडा किरंदुल। छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा मण्डल के एक प्रतिनिधिमंडल ने एनएमडीसी, किरंदुल के अधिशासी निदेशक रविंद्रण नारायण से उनके कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मण्डल ने अपनी आगामी सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें हरेली, पोरा, गणेश पूजा, दशहरा, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस जैसे प्रमुख त्योहारों और विभिन्न खेल आयोजनों का उल्लेख किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने इन आयोजनों को सफल बनाने के लिए एनएमडीसी से सहयोग और प्रोत्साहन की अपेक्षा व्यक्त की। साथ ही, उप महाप्रबंधक नागबेनी से भी मुलाकात कर मण्डल की गतिविधियों और उद्देश्यों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। अधिशासी निदेशक रविंद्रण नारायण ने मण्डल के प्रयासों की सराहना की और क्षेत्रीय संस्कृति व खेल के विकास के लिए भविष्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्रीय सांस्कृतिक और क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने पर सकारात्मक चर्चा हुई।
प्रमुख उपस्थित सदस्य: अध्यक्ष: लोकनाथ चुरेंद्र सचिव: पी.एल. साहू कार्यालय सचिव: डागेन्द्र वर्मा सांस्कृतिक सचिव: देवेन्द्र साहू क्रीड़ा सचिव: पलक राम साहू सदस्य: घनश्याम वर्मा अन्य सम्मानित सदस्य यह मुलाकात क्षेत्रीय संस्कृति और खेल के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नगर पंचायत गुंडरदेही में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा और स्वीकृति पत्र वितरित

भानुप्रताप साहू

बालोद। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी/ग्रामीण) के तहत आवास निर्माण के लिए योग्य हितग्राहियों को आज गुण्डरदेही नगर पंचायत कार्यालय में भवन अनुज्ञा और स्वीकृति

पत्र नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन के द्वारा वितरित किया गया । इस पहल से उन परिवारों के अपने सपनों का घर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिन्हें योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन,सीएमओ किरण पटेल,सब इंजीनियर रूपेश सिंह राठिया , देशमुख ,छम्मन साहू ,पार्षद हरीश निषाद , रोमलाल यादव ,सेवक महिपाल,नगर पंचायत कर्मचारी और प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही उपस्थित रहे । इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन ने हितग्राहियों को उनके नए आवास के लिए शुभकामनाएं दीं और बताया कि अभी वर्तमान में 50 लोगों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है जिसमें से 12 हितग्राहियों को आज भवन अनुज्ञा दिया बाकी बचे हितग्राहियों को भी अतिशीघ्र भवन अनुज्ञा दिया जाएगा ।भवन अनुज्ञा और स्वीकृति पत्र मिलने के बाद हितग्राही अपने आवास का निर्माण कार्य नियमानुसार शुरू कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है, ताकि योजना का लाभ सही और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके।प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के सभी बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से न केवल आवास की समस्या का समाधान हो रहा है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आ रहा है। यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों और वंचितों के लिए एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हितग्राहियों ने सरकार के इस कदम के प्रति आभार व्यक्त किया और खुशी जाहिर की कि अब वे अपने स्वयं के घर का निर्माण कर पाएंगे।

मेरा युवा भारत के तत्वावधान में विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित

महासमुन्द व्यूरो (समय दर्शन)। मेरा युवा भारत महासमुंद के तत्वाधान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोरिंग में आयोजित किया गया। जिसमें भाषण प्रतियोगिता, देश भक्ति गीत प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में हर्ष साहू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं जय विश्वकर्मा, दुर्गा साहू, झरना साहू, चित्रलेखा धीवर ने राज्य गीत एवं देशभक्ति गीत में अपना स्थान बनाया, उक्त आयोजन संस्था के व्यायाम शिक्षक डॉ सुनील कुमार भोई की देखरेख में संपन्न हुई, आयोजन के विजेता छात्र छात्राओं एवं ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण शिविर में शामिल खिलाड़ियों को संस्था के प्राचार्य एवं शिक्षकों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करते समय वरिष्ठ व्याख्याता जे ऐल साहू ने बच्चों के इस प्रकार की सहभागिता पर प्रसन्नता जाहिर की एवं वरिष्ठ व्याख्याता यू आर साहू ने विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेने से बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहयोग होने की बात कही एवं संस्था के प्राचार्य एल एन दीवान ने खुशी जाहिर करते हुए सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी।

नगर पालिका प्रशासन को यात्रियों एवं परिवहन कर्मियों को हो रही विभिन्न असुविधाओं से कराया अवगत

भाटापारा (समय दर्शन)। भाटापारा नगर क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में आज चालक एवं परिचालक संघ द्वारा नगर पालिका प्रशासन को यात्रियों एवं परिवहन कर्मियों को हो रही विभिन्न असुविधाओं से अवगत कराया गया।

निवेदन के उपरांत स्थल पर पहुँचकर स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संघ के पदाधिकारियों एवं परिवहन कर्मियों से विस्तारपूर्वक संवाद कर उनकी समस्याएं गंभीरतापूर्वक सुनी गईं। तत्पश्चात संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए कि बस स्टैंड परिसर में साफ़-सफ़ाई, पेयजल, शौचालय, रैन बसेरा एवं प्रकाश व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधाएं सुलभ कराई जाएं।

साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यात्रियों को सुरक्षित, सहज और सुविधाजनक परिवहन सेवा का अनुभव हो तथा चालक-परिचालकों को सम्मानजनक वातावरण में कार्य करने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि यात्रियों और परिवहन से जुड़े कर्मियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण प्राथमिकता में रखा गया है, और आगामी समय में आवश्यकतानुसार समग्र सुधार कार्य किए जाएंगे। साथ मे नगर पालिका उपाध्यक्ष दिलीप छाबड़िया सभापति मनीष मिश्रा नंदू वैष्णव मोंटू ध्रुव कीर्तन जायसवाल उपस्थित थे।

बिजली दर वृद्धि और कटौती के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, बिजली विभाग का घेराव

किरंदुल (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ के किरंदुल नगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अवधेश गौतम के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने साय सरकार के खिलाफबिजली दरों में वृद्धि और बार-बार हो रही बिजली कटौती के विरोध में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बिजली विभाग का घेराव किया गया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई।

प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर बिजली बिल में हाल ही में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की। इस वृद्धि में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 10 पैसे, व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे और कृषि मीटर पर 50 पैसे की बढ़ोतरी शामिल है। तुलिका कर्मा ने कहा कि साय सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है और बिजली कटौती के साथ-साथ बिल वृद्धि ने लोगों पर दोहरी मार डाली है। उन्होंने सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि जनता इन नीतियों से त्राहिमाम कर रही है।

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र मृणाल राय ने कहा कि कांग्रेस जमीन पर उतरकर सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाएगी और जनहित के लिए संघर्ष जारी रखेगी। इस धरना-प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस प्रभारी सलीम रजा उस्मानी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंदिरा शर्मा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मृणाल राय, जिला प्रवक्ता राहुल महाजन, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पप्पाचन, पार्षद गायत्री साहू, इला पटेल, इंटक से राकेश लाल, बीएल तारम, ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक भास्कर, जमील खान, विप्लब मलिक, पूर्व पार्षद दिनेश प्रसाद, राजू कुंजाम, काजल आनंद, गुलापा साहू, कृष्णा भंडारी, चंदू बघेल, ऋषप राय, संतोष रमैया सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली दरों में वृद्धि को वापस लेने की मांग को दोहराया। यह प्रदर्शन स्थानीय लोगों के बीच भी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि बिजली कटौती और बढ़े हुए बिलों ने आम जनता को परेशान कर रखा है।

भाटापारा शहर में आयोजित किया गया यातायात जागरूकता हेलमेट रैली कार्यक्रम

भाटापारा (समय दर्शन)। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता हेलमेट पहनकर स्वयं निकाली यातायात जागरूकता कार्यक्रम में हेलमेट के प्रति जागरूकता लाने एवं लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने हेतु आयोजित किया गया यातायात जागरूकता हेलमेट रैली कार्यक्रम

इस दौरान दोपहिया वाहन में हेलमेट धारण नहीं करने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 11 वाहन चालकों का काटा गया चालान

पुलिस अधीक्षक द्वारा दोपहिया वाहन चालकों को किया गया हेलमेट का वितरण

भाटापारा शहर में यातायात जागरूकता हेलमेट रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हेलमेट रैली का प्रतिनिधित्व पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता द्वारा किया गया। उन्होंने स्वयं हेलमेट पहनकर एवं स्कूटी चलाते हुए शहर का भ्रमण कर लोगों से दोपहिया वाहन चालन के दौरान हेलमेट पहनने की अपील की गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य हेलमेट के प्रति जागरूकता लाना एवं अधिक से अधिक लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल चौंक भाटापारा में दोपहिया वाहन में हेलमेट धारण नहीं करने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 11 वाहन चालकों का चालान काटा गया। इसके साथ ही भावना गुप्ता द्वारा वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरण किया गया। पुलिस टीम द्वारा हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन कर भाटापारा शहर में प्रमुख मार्ग एवं चौक चौराहों का भ्रमण किया गया एवं लोगों से मोटरसाइकिल चालन के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की गई भाटापारा यातायात पुलिस की अपील सुरक्षित एवं सुगम परिवहन के लिए यातायात नियमों का सदैव पालन आवश्यक है, इससे आमजनों द्वारा अनुशासित होकर वाहन चालन किया जाएगा, *जिले में सुरक्षित परिवहन के लिए आमजनों का भी परस्पर सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

महाराष्ट्र मंडल का पौधरोपण अभियान अगले हफ्ते से

एक हजार पौधे रोपण के साथ उनके संरक्षण का भी लिया जाएगा जिम्मा

रायपुर (समय दर्शन)। महाराष्ट्र मंडल की पर्यावरण समिति ने मानसून सत्र में राजधानी रायपुर में एक हजार पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। समिति की ओर से पौधरोपण का भव्य आयोजन चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरे एक फार्म हाउस में किया जाएगा, जहां लगभग 300 पौधों का रोपण मंडल की कार्यकारिणी, विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों के साथ आजीवन सभासद भी करेंगे। ये समिति न सिर्फ पौधों का रोपण करेगी बल्कि उनके संरक्षण की भी पूरी व्यवस्था करेगी। पर्यावरण समिति के समन्वयक अभय भागवतकर ने बताया कि इस बार स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, सड्डू कॉलोनी, शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल दतरेंगा, गवर्नमेंट स्कूल

मठपुरैना, श्री सोलापुरी माता मंदिर डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, शासकीय दूधाधारी महिला महाविद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम रोहिणीपुरम, संभव पाइप्स इंडस्ट्री उरला, लिंगराज स्टील्स उरला जैसे अनेक स्थलों पर यथासंभव पौधारोपण करने की तैयारी है। संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं, इंडस्ट्री के प्रमुखों से पहले की इसके लिए स्वीकृति ली जा चुकी है।

पर्यावरण समिति पुरुष के प्रमुख वैभव बर्वे ने जानकारी दी कि महाराष्ट्र मंडल में 19 अगस्त को आयोजित मंगलागौर की पूजा में शामिल होने वाले लगभग 30 नवविवाहित जोड़ों को भी इस अवसर पर उपहार स्वरूप गमलों में पौधे दिए जाएंगे। पर्यावरण समर्िति की ओर से यह आश्वस्त किया गया है कि इस बीच यदि किसी संस्था की ओर से पौधारोपण के लिए बुलाया जाता है तो हमारी टीम वहां पौधे रोपने जरूर जाएगी। इसी तरह यदि किसी को हमसे पौधों की अपेक्षा है, तो वो भी हम देने की प्रयास करेंगे।

पर्यावरण समिति महिला प्रमुख अनघा करकशे के अनुसार पर्यावरण समिति खुले मैदानों, खेत- खलिहानों या ऐसे किसी स्थान पर पौधों का रोपण नहीं करती, जहां कभी भी मवेशी आकर पौधों को चर जाएं। महाराष्ट्र मंडल की ओर से अब तक लगभग साढ़े सात हजार पौधों रोपे गए हैं। उनमें से ज्यादतर वृक्ष बन गए हैं या उस ओर अग्रसर हैं। दरअसल पौधे रोपने के बाद पर्यावरण समिति के सदस्य समय-समय पर रोपे गए पौधों की स्र्थिति देखने रोपण स्थल पर जाते रहते हैं और किसी भी तरह की कमी को तत्काल पूरा भी करते हैं।

विधानसभा में सुनील सोनी ने कहा

राज्य में आए दिन हो रहे साइबर क्राइम, विशेषज्ञ की नियुक्ति का अता पता नहीं...

रायपुर (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे साइबर अपराध के मुद्दे को भाजपा विधायक सुनील सोनी ने आज विधानसभा में उठाया। सोनी ने कहा कि प्रदेश में आए दिन साइबर अपराध हो रहे हैं और अब तक किसी साइबर विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं हो पाई है।

प्रश्नकाल में सुनील सोनी का सवाल था कि जनवरी 2024 से जून 2025 तक छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के कुल कितने केस दर्ज किए गए? उन पर लगाम लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या इस अपराध में बैंक कर्मियों की भी भूमिका पाई गई है? जनवरी 2024 से 20 जून 2025 तक कुल कितनी राशि के साइबर अपराध के प्रकरण दर्ज किए गए हैं? राजधानी रायपुर में साईबर अपराध के कुल कितने केस दर्ज हुए हैं? उप मुख्यमंत्री (गृह) विजय शर्मा की ओर से जवाब आया कि प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के कुल 1301 अपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कुछ अपराधों में बैंक कर्मियों की भूमिका पाई गई है। 107 पीड़ितों को उनकी राशि वापस दिलाई गई है। राजधानी रायपुर में साइबर अपराध के कुल 147 केस दर्ज हुए हैं।

सोनी ने पूछा कि इतने बड़े राज्य में कोई साइबर विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया है। क्या इस काम के लिए किसी आईपीएस स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है? साइबर थाने कहां-कहां पर हैं? उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसम्बर 2024 में राजधानी रायपुर में आधुनिक तकनीकी से लेस साइबर भवन का उद्घाटन हुआ है। आईपीएस स्तर के अधिकारी ही साइबर विशेषज्ञ की भूमिका में रहेंगे। अभी इनपैनलमेंट की प्रक्रिया कर रहे हैं। साइबर अपराध पर रोक के लिए एक आईपीएस अफसर एवं 5 वरिष्ठ अधिकारी ट्रेनिंग लेकर आए हैं। जिलों में साइबर थाने नहीं साइबर सेल का ज़रूर गठन किया गया है। सोनी ने पूछा कि प्रदेश में जो रेगूलर थाने हैं वो साइबर अपराधों को देख पाने में क्या सक्षम हैं? मीडिया से मालूम हुआ कि साइबर अपराध नियंत्रण केन्द्र का एड्रेस पीएचक्यू दिया हुआ है। क्या साइबर अपराध में थाने का स्टाफविवेचना कर किसी को गिरफ्तार करने में सक्षम है? उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 साइबर थानों की स्वीकृति मिली हुई है। 5 का काम चल रहा है। सोनी ने कहा कि आपने अपने जवाब में स्वीकार किया कि साइबर अपराधों में बैंक के कर्मचारियों की भी संलिप्तता है। अब तक साइबर अपराध में संलिप्त कितने अधिकारियों-कर्मचारियों को जेल में डाला गया है? उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर 1, दुर्ग 1 एवं बिलासपुर 1 कुल 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन 3 मामलों में 7 लोगों को जेल में डाला गया है।

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ राज्य का रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए यहां के पुलिस अफ्सरों को हैदराबाद भेजा गया। पिछले डेढ़ साल में राज्य में 107 लोग साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं। आपने बताया कि ठगी के शिकार लोगों को 3 करोड़ की राशि वापस दिलाई गई है। यह आंकड़ा काफी कम लगता है। इस पर नियंत्रण के लिए आईजी स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सही है कि ठगी के शिकार हुए 107 लोगों को 3 करोड़ 69 लाख वापस हुए हैं। सारा कुछ अदालत से क्लीयर हो जाने के बाद ही राशि लौटाने का काम होता है, जो लगातार चलते रहता है। साइबर नियंत्रण के लिए आईजी स्तर के अधिकारी को ही जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में 28 फरवरी को इसी संबंध में मेरा प्रश्न लगा था जिसमें जवाब आया था कि साइबर विभाग में साइबर विशेषज्ञ की नियुक्ति किए हैं और अभी बता रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है। यदि छत्तीसगढ़ के छह लोग प्रशिक्षण लेकर लौट चुके हैं तो साइबर शाखा में नियुक्ति कब तक होगी? उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 आईपीएस समेत 5 अफ्सरों की नियुक्ति जल्द कर दी जाएगी।

रायपुर को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने केंद्रीय मंत्री से मिले सांसद बृजमोहन

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्थापना की रजत जयंती से पहले राजधानी रायपुर को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात कर यह मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि रायपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने से राज्य के आर्थिक विकास और वैश्विक संपर्क को नई उड़ान मिलेगी।

रायपुर एयरपोर्ट को लेकर प्रमुख मांगें:

1 नवंबर से पहले रायपुर को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाए

रायपुर एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाए और एक नया टर्मिनल तैयार किया जाए

रायपुर से बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर के बीच हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए

रायपुर में अंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवा शुरू की जाए

भिलाई के लिए फ्लाइंग स्कूल का प्रस्ताव

सांसद अग्रवाल ने भिलाई के नंदनी एयरपोर्ट में एक फ्लाइंग स्कूल खोलने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में एविएशन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को उड़ान प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे।

क्या बोले बृजमोहन अग्रवाल?

सांसद ने कहा कि रायपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलने से न केवल व्यापार और उद्योग को बल मिलेगा, बल्कि पर्यटन और निवेश को भी गति मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवा शुरू होने से किसानों और कारोबारियों को भी बड़ा फायदा होगा।

मंत्री ने दिए सकारात्मक संकेत

केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन देते हुए कहा कि रायपुर जैसे तेजी से विकसित होते शहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर की हवाई सेवाएं मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पर जल्द कदम उठाए जाएंगे।

एयरपोर्ट कमेटी मेंबर भी रहे मौजूद

इस मुलाकात में रायपुर एयरपोर्ट कमेटी के सदस्य और एविएशन एक्सपर्ट डॉ. सुमीत सुशीलन भी शामिल रहे। उन्होंने तकनीकी पहलुओं पर भी जानकारी दी और बताया कि रायपुर एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय दर्जे के लिए पूरी तरह सक्षम है।

छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस से पहले रायपुर को अंतरराष्ट्रीय हवाई मानचित्र पर लाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं।

मुख्यमंत्री से केंद्रीय भूमि संसाधन सचिव ने की भेंट, कई विषयों पर हुई चर्चा

रायपुर। मुख्यमंत्री साय से मंगलवार को विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने भेंट की। इस अवसर पर भू-अभिलेख प्रणाली को सुदृढ़ करने, भूमि सर्वेक्षण में तकनीकी नवाचारों के उपयोग, तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार भू-राजस्व दस्तावेजों को अद्यतन करने और आवश्यक सुधार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड जितने व्यवस्थित होंगे, राजस्व न्यायालयों में मामलों का निपटारा उतना ही शीघ्र और प्रभावी रूप से हो सकेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि अभिलेखों में सुधार संबंधी केंद्र सरकार की सभी पहल के साथ राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी, ताकि यह प्रणाली और अधिक प्रभावशाली व जनहितकारी बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तकनीक आधारित नवाचारी पहलों के माध्यम से भू-राजस्व रिकॉर्ड में पारदर्शिता, गति और सटीकता लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसानों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस दिशा में सभी आवश्यक कदम तत्परता से सुनिश्चित करें। केंद्रीय भूमि संसाधन सचिव मनोज जोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से इसमें और अधिक सुधार लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में पारंपरिक पद्धति से किए जाने वाले भूमि सर्वेक्षण में समय अधिक लगता था, किंतु अब आधुनिक तकनीकों के उपयोग से यह प्रक्रिया तेज़, अधिक सटीक और भरोसेमंद हो गई है। जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार भू-अभिलेख संधारण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान नक्शों के अद्यतन में कई बार तकनीकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें डिजिटल सर्वेक्षण के माध्यम से प्रभावी रूप से दूर किया जा सकेगा। इससे प्रत्येक नागरिक को अद्यतन और प्रमाणिक नक्शा प्राप्त होगा, जिससे गड़बड़ियों में कमी आएगी और शहरी क्षेत्रों के विस्तार को बेहतर ढंग से नियोजित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री से राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों ने की भेंट

रायपुर। मुख्यमंत्री साय से विधानसभा स्थित कार्यालय में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों ने भेंट कर मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2005 से 2009 बैच तक के अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने के निर्णय हेतु आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री शर्मा भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के समुचित प्रबंधन हेतु 30 सांख्येतर पदों का सृजन करते हुए वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय उन अधिकारियों के लिए लिया गया है जिन्होंने सेवा में निर्धारित अर्हता अवधि पूर्ण कर ली है।

छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण को लेकर तीन दिवसीय समीक्षा दौरे पर आए केंद्रीय भूमि संसाधन सचिव मनोज जोशी

केंद्रीय सचिव ने छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेख डिजिटलीकरण के दिए निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण को लेकर तीन दिवसीय समीक्षा दौरे पर आए केंद्रीय भूमि संसाधन सचिव मनोज जोशी ने राज्य सरकार और अधिकारियों को पारदर्शिता, अद्यतन रिकॉर्ड उपलब्धता और तेज कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर दिया कि यह प्रक्रिया न सिर्फ प्रशासनिक दक्षता बल्कि किसानों और आम नागरिकों के हितों से भी जुड़ी है।

मनोज जोशी एवं संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी ने 15 जुलाई को न्यू सर्किट हाऊस नवा रायपुर में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) तथा 'नक्शा परियोजना' की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत,महानिरीक्षक पंजीयन पुष्पेंद्र मीणा,भू संचालक विनीत नन्दनवार, भूमि संसाधन विभाग के डॉ. एम.के.स्टॅलिन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान केंद्रीय सचिव भूमि संसाधन मनोज जोशी विभागीय अधिकारियों के साथ भू-अभिलेख के संधारण, सर्वे आदि की प्रगति की विस्तृत समीक्षा एवं परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के लिए अनावश्यक तिथि बढ़ाये जाने की परंपरा को रोका जाए। जिओरिफ्रेंसिंग के कार्य को पूर्ण कर किसानों के हित मे उपयोग करें। इसके लिए ध्यान रखें कि भूमि के क्षेत्र और सीमा में वेरिएशन कम से कम हो। जमीन से संबंधित प्रकरणों को निराकृत करने के लिए विशेष राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। राज्य में भूमि सर्वे या रिसर्वे के कार्यो को क्षेत्रानुसार अलग-अलग वेंडरों को दिया जाय ताकि काम समय पर पूरा हो। उन्होंने कहा कि राज्य में भूमि सर्वे या रिसर्वे के काम को प्रशासन द्वारा कुछ गांव को मॉडल के रूप में लेकर भी किया जा सकता है। इसी तरह जमीन दस्तावेजों के साथ भू-स्वामियों के बारे में यथा आधार कार्ड,मोबाइल नंबर आदि की सम्पूर्ण जानकारी को सुरक्षित रखा जाए। इस जानकारी का उपयोग भू-स्वामियों के लिए जमीन के उपयोग,बैंक ऋण या खरीदी-बिक्री आदि में हो सकेगा।इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण और नक्शा परियोजना की प्रगति को गति देना तथा सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि केंद्रीय राजस्व सचिव 14 से 16 जुलाई तक राज्य के दौरे में हैं। इस महत्वपूर्ण दौरे का उद्देश्य राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, पारदर्शिता तथा अद्यतन भू-अभिलेखों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है ताकि आमजन को समयबद्ध एवं सुगम सेवाएं प्राप्त हो सकें। छत्तीसगढ़ शासन एवं संबंधित विभागों द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह समीक्षा बैठक मील का पत्थर सिद्ध होगी।

संक्षिप्त समाचार

विधानसभा में शेषराज हरवंश ने उठाया मामला

सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में कैंसर जांच मशीन तक ठीक नहीं

रायपुर (समय दर्शन)। राजधानी रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल (मेकाहारा) में जांच उपकरणों के खराब पड़े रहने का मामला आज विधानसभा में कांग्रेस विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश ने उठाया। श्रीमती हरवंश ने चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश के इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कैंसर की जांच करने वाली मशीन तक ठीक नहीं। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश का सवाल था कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा रायपुर में मरीजों को जांच की सुविधा देने हेतु कुल छोटी, बड़ी एवं मध्यम जांच मशीनें कितनी मात्रा में लगाई गई हैं? जून 2025 की स्थिति में कितनी जांच मशीनें चालू हैं? कितनी बन्द हैं? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की ओर से जवाब आया कि मेकाहारा में छोटी बड़ी/मध्यम कुल 161 मशीनें उपलब्ध हैं। जून 2025 की स्थिति में 111 मशीनें चालू हैं एवं 50 मशीनें बंद है। शेषराज हरवंश ने कहा कि मेकाहारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। जहां कैंसर जांच वाली मशीन तक ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले सरकार के समय में 20 करोड़ की मशीन बिना स्वीकृति के खरीद ली गई थी। वह आठ साल से चालू नहीं हो पाई। उसे चालू करवाएंगे। श्रीमती हरवंश ने कहा कि यह मशीन 9 साल पहले आई थी। उस समय आप ही लोगों की सरकार थी। अब तक चालू कैसे नहीं हो पाई? स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- हमने भवन बनवा दिया था। करना आप लोगों को था। आप की सरकार में कुछ हुआ नहीं। स्वास्थ्य मंत्री की इस बात के विरोध में विपक्षी विधायकगण शोर मचाने लगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि माना हमारे पिछले कार्यकाल के समय में इस पर काम शुरु हुआ। लेकिन आगे दुर्भावनावश इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। रेडियेशन मशीन खराब है। इसे ठीक कराने बात चल रही है।

छत्तीसगढ़ में रेत खनन व्यवस्था को मिल रहा नया स्वरूप

रायपुर। राज्य में रेत खनन नीति को अधिक पारदर्शी, संगठित, पर्यावरण-संवेदनशील और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से व्यापक कदम उठाए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार के शासन काल के दौरान राज्य में संचालित रेत खदानों की संख्या 300 से घटकर लगभग 100-150 रह गई थी, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हुए और अवैध खनन को बढ़ावा मिला। वर्तमान सरकार द्वारा खनिज नीति में सुधार कर रेत खनन की व्यवस्था को संगठित, नियंत्रित और जनहितकारी बनाया गया है।

पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में तीव्रता- राज्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया को गति देने के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर तीन राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण समितियों का गठन किया गया है। पूर्व में केवल एक समिति कार्यरत थी। इस निर्णय से लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे की प्रक्रिया सुगम हुई है।

वैध खदानों की संख्या में वृद्धि- वर्तमान में 119 रेत खदानें पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ विधिवत संचालित हैं, जबकि 94 अन्य खदानों की मंजूरी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। साथ ही, आगामी 1 से 1.5 वर्षों में 300 से अधिक नई खदानों को स्वीकृति दिए जाने की योजना है, जिससे रेत की आपूर्ति सुलभ बनी रहेगी और निर्माण कार्यों को गति मिलेगी।

द्धद्धञ्ज रुड़की की रिपोर्टः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खनन-प्रमुख नदियों पर खनन के पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर द्धद्धञ्ज रुड़की से कराए गए अध्ययन में यह निष्कर्ष सामने आया है कि विधिवत और नियंत्रित रेत खनन से नदियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। यह रिपोर्ट राज्य की वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित खनिज नीति को समर्थन प्रदान करती है।

अवैध खनन पर सख्त कार्यवाही- वर्ष 2024-25 से जून 2025 तक 6,331 अवैध खनन प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से ?18.02 करोड़ की वसूली, 184 मशीनों की जब्ती, 56 एफआईआर तथा 57 न्यायालयीन परिवाद दायर किए गए। जिला एवं राज्य स्तरीय टास्क फोर्सों द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है, जिसमें खनिज, राजस्व, पुलिस, परिवहन और पर्यावरण विभाग के अधिकारी सम्मिलित हैं।

विवादों पर त्वरित कार्यवाही- राजनांदगांव और बलरामपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में रेत से संबंधित विवादों एवं घटनाओं पर त्वरित कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही की गई है। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रॉयल्टी में राहत- 15 मार्च 2024 को लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को रेत पर रॉयल्टी से छूट प्रदान की गई है। इस निर्णय से गरीबों और जरूरतमंदों को प्रत्यक्ष राहत मिली है।

भविष्य की नीतिः पारदर्शिता और संतुलन- छत्तीसगढ़ शासन की नीति स्पष्ट है – खनिज संसाधनों के दोहन को जनहित, पारदर्शिता और पर्यावरणीय संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित करना।

संगठित, वैज्ञानिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से तैयार की गई यह नई रेत खनन नीति राज्य के समग्र विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए सशक्त आधार बनेगी।

संपादकीय

ठाकरे भाई साथ साथ

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने त्रिभाषा फार्मूले द्वारा मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की योजना का आरोप लगाया। हिन्दी को अनिवार्य बनाने के फैसले के विरोध में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मार्च निकालने की तैयारी में थे। मगर सरकार के फैसला वापस करने के बाद विजय रैली निकाली जिसमें शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ने कहा कि अब हम एक-दूसरे का साथ देने के लिए आ गए हैं। मिल कर आपको (सरकार) बाहर कर देंगे। राज ने कहा, किसी भी झगड़े या विवाद से महाराष्ट्र बड़ा है। हम बीस साल बाद साथ आ रहे हैं। जो काम बाला साहेब नहीं कर सके, वह देवेंद्र फडनवीस ने कर दिखाया। आपसी अनबन के दो दशक लंबे अंतराल के बाद दोनों नेताओं ने मंच साझा किया। भाजपा ने इसे खोए आधार को वापस पाने की हताश कोशिश और पारिवारिक मेल-मिलाप सरीखा ठहराया। उद्धव ने अपने संबोधन में कहा कि हम किसी को धमकाएंगे नहीं, लेकिन उनको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमें धमकाते हैं। उन्होंने सभी मराठियों को साथ आने, मराठियों की पहचान को मिटना नहीं चाहिए जैसी बातें कीं जबकि राज ने मराठी को अपना एकमात्र एजेंडा बताया और कहा, हम महाराष्ट्र को बंटता हुआ नहीं देखना चाहते। असल सवाल है, दोनों ठाकरे पुराने सारे मतभेद मिटा कर साथ कैसे काम करते हैं। हालांकि, दोनों चचेरे भाइयों का आनन-फानन मंच साझा करना, शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने वाले ठाकरे बंधुओं को इसका प्रतिफल तो जनता ही देगी क्योंकि मात्र भाषा के मुद्दे से देशवासियों को प्रभावित कर पाना आसान नहीं है। दूरगामी राजनीति करने के लिए ठाकरे बंधुओं को भाजपा गठबंधन को चुनौती देने के लिए बड़े मुद्दे तलाशने होंगे। मराठी मानुष के पक्षधर रहे बाल ठाकरे जिस हिन्दुत्व का बखान करते रहे थे, यह राग बिल्कुल उसके विपरीत जाता प्रतीत हो रहा है। मराठी बोलने को लेकर हाथापाई और अभद्रता के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर जनता में नाराजगी है। मुंबई में उत्तर भारतीयों ही नहीं, दक्षिण भारतीयों के वोट बैंक को कई दशकों से तवज्जो दी जा रही है। हालांकि सत्ता के लिए गठजोड़ करना आम है परंतु ठाकरे परिवार की राजनीति ढुलमुलाती नजर आ रही है। तमाम कट्टरता के बाजूद राज को पिछले चुनावों में मिली करारी मात को भी नहीं भूलना चाहिए। भाषा, वेशभूषा या रहन-सहन के आधार पर देश को बांटा जाना उचित नहीं कहा जा सकता।

दावों के बावजूद हर साल जलभराव

पंकज चतुर्वेदी

बीते डेढ़ महीने में राजधानी दिल्ली पर कुल चार बार ठीकठाक बादल बरसे और बमुश्किल एक घंटे की बरसात में ही दिल्ली ठिठक गई। तीन दशकों से लाख दावों के बावजूद हर साल जलभराव वाले स्थानों की संख्या बढ़ रही है। 2023 में जहां जलभराव के 308 बिंदु चिन्हित किए गए थे, वहीं 2025 में इनकी संख्या बढ़ कर 410 हो गई है। अब तो डूबने का दायरा वीआईपी कहलाने वाली लुटियन दिल्ली तक आ गया है। पानी भरते ही दो बातें सामने आती हैं। एक तो इस महीने या फिर इतने कम समय में इतना अधिक पानी कितने साल बाद बरसा। दूसरा, नायलॉन की सफाई और सीवर तंत्र का पुराना होना। समझना होगा कि दिल्ली बसी ही इसलिए थी कि यहां से यमुना बह रही थी। दिल्ली का जलभराव हो या फिर प्यास, उसका एकमात्र इलाज यमुना ही है। दिल्ली में जलभराव का कारण यमुना का गाद और कचरे के कारण इतना उथला हो जाना है कि महज एक लाख क्यूसेक पानी आ जाए तो इसमें बाढ़ आ जाती है। नदी की जल ग्रहण क्षमता को कम करने में बड़ी मात्रा में जमा गाद (सिल्ट), रेत, सीवरेज, पूजा-पाठ सामग्री, मलबा और तमाम तरह के कचरे का योगदान है। नदी की गहराई कम हुई तो इसमें पानी भी कम आता है। आजादी के 77 साल में कभी भी नदी की गाद साफ करने का कोई प्रयास हुआ ही नहीं, जबकि नदी में कई निर्माण परियोजनाओं के मलबे को डालने से रोकने में एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश नाकाम रहे हैं। 1994 से लेकर अब तक यमुना एक्शन प्लान के तीन चरण आ चुके हैं, हजारों करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं पर यमुना में गिरने वाले दिल्ली के 21 नालों की गाद भी अभी तक नहीं रोकी जा सकी। जब महानगर के बड़े नाले गाद से बजबजाते हैं, तो जलभराव की चोट दोधारी होती है। जब नाले का पानी नदी की तरफ लपकता है, और उथली नदी में पहले से ही नाले के मुंह तक पानी भरा होता है। ऐसे में नदी के प्रवाह से उपजे प्रतिगामी बल से नाले फिर पलट कर सड़कों को दरिया बना देते हैं। कभी यमुना का बहाव और हाथी डुब्बा गहराई आज के मयूर विहार, गांधी नगर, ओखला, अक्षरधाम तक हुआ करता था। एक तरफ ढेर सारी वैध-अवैध कालोनियों और सरकारी भवनों के कारण नदी की चौड़ाई कम हुई तो दूसरी तरफ गहराई में गाद भर दी। इस तरह जीवनदायी बरसात के जल को समेटने वाली जल धार को कूड़ा ढोने की धार बना दिया गया। वहीं शहर के छह सौ से अधिक तालाब-झीलों तक बरसात का पानी आने के रास्ते रोक दिए गए। दुर्भाग्य है कि कोई भी सरकार दिल्ली में आबादी को बढ़ने से रोकने पर काम कर नहीं रही। इसका खमियाजा भी यमुना को उठाना पड़ रहा है, हालांकि इसकी मार भी उसी आबादी को पड़ रही है। सभी जानते हैं कि दिल्ली जैसे विशाल आबादी वाले इलाके में हर घर पानी और मुफ्त पानी बड़ा चुनावी मुद्दा है, और जब नदी-नहर पानी की कमी पूरी कर नहीं पाते तो जमीन में छेद कर पानी उलिछा जाता है, यह जाने बगैर कि इस तरह भूजल स्तर से बेपरवाही का असर यमुना के जल स्तर पर ही पड़ रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक शोध के मुताबिक, यमुना के बाढ़ क्षेत्र में 600 से अधिक आर्द्रभूमि और जल निकाय थे, लेकिन उनमें से 60त्न से अधिक अब सूखे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, 'यमुना बाढ़ क्षेत्र में यमुना से जुड़ी कई जल-तिजोरियों का संपर्क तटबंधों के कारण नदी से टूट गया।' समझना होगा कि अरावली से चल कर नजफगढ़ झील में मिलने वाली साहबी नदी और इस झील को यमुना से जोड़ने वाली नैसर्गिक नहर का नाला बनना हो या फिर सराय कालेखां के पास बारापुला या फिर साकेत में खिड़की गांव का सतपुला या फिर लोधी गार्डन की नहरें, असल में ये सभी यमुना में जब कभी क्षमता से अधिक पानी आ जाता था तो उसे जोहड़-तालाब में सहेजने का जरिया थीं।

अमर्यादित नहीं हो सकती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

लोकेन्द्र सिंह राजपूत

जब हम विरोध, आलोचना और असहमति के वास्तविक स्वरूप को भूलते हैं तब हमारी अभिव्यक्ति घृणा और नफ़रत में बदल जाती है। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय विचार के संगठनों एवं कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी का स्वर ऐसा ही दिखायी पड़ रहा है, जो अमर्यादित है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी ही अमर्यादित अभिव्यक्ति के मामलों की सुनवाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं है, जिन पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है। इस पर किसी प्रकार के बाहरी प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि इसी प्रकार अमर्यादित लिखा-पढ़ी, बयानबाजी और कार्टूनबाजी जारी रही तब समाज में वैमनस्य और सांप्रदायिक तनाव को फैलने से रोकने के लिए कुछ न कुछ युक्तियुक्त प्रबंध करने ही पड़ेंगे। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी को भी अमर्यादित और असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। नागरिकों को भी समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक मर्यादा है, उसे लांघना किसी के भी हित में नहीं है। उचित होगा कि नागरिक समाज इस दिशा में गंभीरता से चिंतन करे। सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल समाज में नफ़रत और विघटन को जन्म दे सकता है। इसलिए नागरिकों को चाहिए कि वे जिम्मेदारी से बोलें, संयम रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। हमारे यहाँ तो महापुरुषों ने भी कहा है कि जो व्यवहार हम अपने लिए अपेक्षित करते हैं, वही व्यवहार हमें सामने वाले के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के सामने आया वजाहत खान का मामला ऐसा ही है, जिसमें हिन्दू देवी पर तो आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा है लेकिन इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा है। जब पलटकर किसी ने हिन्दू धर्म का अपमान करने के आरोप में उसके खिलाफ एफ़आईआर दर्ज करा दी, तो वह न्यायालय में पहुँच गया है। याद हो कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भावावेश में आकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि जब उसे अपनी गलती का अहसास हुआ तो उसने बिना शर्त माफ़ी भी माँग ली और अपना वह वीडियो भी हटा लिया था। लेकिन इसके बावजूद वजाहत खान ने उसके खिलाफ एफ़आईआर दर्ज करा दी थी। हालांकि ऐसा करते समय वजाहत खान ने अपने गिरेबां में झांककर नहीं देखा कि वह क्या कर रहा है? जब आप अपनी आस्था पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी सुनना पसंद नहीं करते तब आपको दूसरों के देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करने का अधिकार किसने दे दिया है? अच्छा ही हुआ कि वजाहत खान जैसों को आईना दिखाने के लिए हिन्दू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने पर उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज करा दिया गया है। अब उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मोल समझ आएगा। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा है कि लोगों को हेट स्पीच क्यों अटपटे और गलत नहीं लगते हैं। ऐसे कंटेंट पर नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही लोगों को भी ऐसे नफ़रत भरे कंटेंट को शेयर करने और लाइक करने से बचना चाहिए।

इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के बेहद आपत्तिजनक कार्टून को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सख्त टिप्पणी की है। न्यायालय ने कार्टूनिस्ट की मानसिकता पर प्रश्न उठाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बनाए गए इस आपत्तिजनक कार्टून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आजकल कार्टूनिस्ट और स्टैंडअप कॉमेडियन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या ये लोग कुछ भी बनाने और बोलने से पहले सोचते नहीं है? न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस प्रकार के घृणित व्यंग्य चित्रों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हेमंत मालवीय के कार्टून में कोई परिपक्वता नहीं है। ये वास्तव में भड़काऊ है। याद हो कि इस कार्टूनिस्ट के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय भी फटकार लगा चुका है। उच्च न्यायालय ने जब कार्टूनिस्ट की जमानत याचिका खारिज की तो उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन यहाँ भी उनके कृत्य पर कोई राहत नहीं मिली है। हेमंत मालवीय के कार्टून में कोई कलात्मक अभिव्यक्ति भी नहीं है। अपनी वैचारिक और राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए इस प्रकार के लोग कला को भी बदनाम करते हैं, जो अभिव्यक्ति की सशक्त माध्यम हैं। मजेदार तथ्य यह कि हेमंत मालवीय का बचाव कर रहे उनका भी वकील यह मानता है कि हाँ, ये घटिया कार्टून है। लेकिन क्या ये अपराध है? नहीं, यह अपराध नहीं हो सकता। यह आपत्तिजनक हो सकता है लेकिन अपराध नहीं। अब यह अपराध है या नहीं, यह तो न्यायालय तय करेगा लेकिन मालवीय का वकील कम से कम यह तो स्वीकार ही कर रहा है कि कार्टून घटिया है। आरोप यह हैं कि उनका कार्टून प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रीय संगठन का अपमान ही नहीं करता है अपितु सांप्रदायिकता को भी भड़काता है। हेमंत मालवीय की शिकायत दर्ज करानेवाले सामाजिक कार्यकर्ता विनय जोशी आरोप लगाए हैं कि मालवीय ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा। उनकी ओर से दर्ज करायी गई एफ़आईआर में कई 'आपत्तिजनक' पोस्ट का उल्लेख किया गया है, जिनमें भगवान शिव पर कथित रूप से अनुचित टिप्पणियों के साथ-साथ मोदी, आरएसएस कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के बारे में कार्टून, वीडियो, तस्वीरें और टिप्पणियाँ शामिल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हेमंत मालवीय ने पहली बार आपत्तिजनक कार्टून नहीं बनाया था, बल्कि यह उनका नियमित अभ्यास है। न्यायालय के अनुसार, इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है।

बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय की इस सलाह पर नागरिक समाज को न केवल चिंतन-मनन करना चाहिए अपितु उसका अनुकरण भी करना चाहिए- नागरिकों को अपनी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की कीमत समझनी चाहिए और इसके साथ-साथ स्व-नियंत्रण और संयम का पालन करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर बढ़ती विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को कहा है कि वे नफ़रत फैलाने वाले भाषणों को रोकें। हालांकि न्यायालय ने किसी भी प्रकार की सेंसरशिप की बात से इनकार किया। यानी नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए न्यायालय ने वकीलों एवं सरकारों से सुझाव भी माँगे हैं। हालांकि यह राह बहुत कठिन है कि सरकार किसी प्रकार का प्रतिबंध भी न लगाए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नफ़रती सोच पर लगाम भी लगा ले। इस दिशा में यदि कहीं कोई राह दिखायी देती है, तो वह जागरूक नागरिक समाज है। समाज को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे आना होगा। जब नफ़रती भाषण करनेवालों को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा हतोत्साहित किया जाने लगेगा, तब बहुत हद तक इस पर नियंत्रण हो जाएगा। यहाँ राष्ट्रीय विचार के कार्यकर्ताओं के धैर्य की सराहना करनी होगी कि वे नफ़रत की बौछारों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जबकि अन्य विचार या संप्रदाय के प्रति अमर्यादित बयानबाजी होती है, तो तत्काल उग्र प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। शायद इसलिए ही सबने हिन्दू धर्म, हिन्दू संगठन और हिन्दू समाज को पंचिंग बैग समझ लिया है। इस पर लगाम लगनी ही चाहिए। बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय के इस आग्रह का पालन व्यापक स्तर पर हम सबको करना चाहिए, जिसमें न्यायालय ने कहा कि लोग स्वयं से जिम्मेदारी निभाएं और अपनी बातों में संयम बरतें।

सस्ते कर्ज से बढ़ेगी आर्थिक रफ्तार

डा. जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों भारत के विकास से संबंधित प्रकाशित हो रही रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि अब भारत में सस्ते कर्ज से आर्थिक रफ्तार बढ़ेगी। पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए रेपो रेट में 50 आधार अंकों यानी 0.50 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया है। अब रेपो रेट 6 प्रतिशत से घटकर 5.5 प्रतिशत हो गई है। इस वर्ष 2025 में फ़रवरी से अब तक लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती हुई है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में भी एक प्रतिशत की बड़ी कटौती करते हुए इसे तीन प्रतिशत के स्तर पर ला दिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और सीआरआर में बड़ी कटौती करके तेज विकास की जरूरत और महंगाई के बीच बुद्धिमतापूर्ण समीकरण स्थापित किया है। इससे बाजार मांग में मजबूती और निवेश के नए माहौल को बल मिलेगा। यही कारण है कि रिजर्व बैंक के नए मौद्रिक उपायों के बाद शेयर बाजार में उछाल आया है। इस समय आरबीआई के द्वारा ब्याज दर घटाने के कई महत्वपूर्ण आधार हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की खुदरा महंगाई अप्रैल 2025 में घटकर 3.16 प्रतिशत पर आ गई है। मई में खुदरा महंगाई दर सिर्फ 2.82 प्रतिशत रही। मई 2025 की खाद्य महंगाई दर अक्टूबर 2021 के बाद से सबसे कम है।

क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार, शाकाहारी थाली की कीमत इस साल जून में 27.1 रुपए रही, जो पिछले साल जून में 29.4 रुपए की थी। हालांकि, इस साल मई के 26.2 रुपए की तुलना में यह महंगी हो गई है। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में सबसे अधिक गिरावट आने से घर में बन रही शाकाहारी और मांसाहारी थाली की लागत जून में सालाना आधार पर घट गई है। इसी तरह, मांसाहारी थाली इस साल जून में 54.8 रुपए की रही, जो पिछले साल इसी महीने में 58 रुपए की थी। हालांकि, यह भी मई के 52.6 रुपए की तुलना में महंगी हो गई है। टमाटर एक साल में 42 रुपए से 24 फ़ीसदी गिरकर 32 रुपए किलो हो गया है, लेकिन मासिक आधार पर 36 फ़ीसदी महंगा है, क्योंकि आवक में आठ फ़ीसदी की भारी कमी आई है। यह बात महत्वपूर्ण है कि रिकॉर्ड कृषि उत्पादन और अच्छा मानसून भी ब्याज दर में कमी का कारण है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2024-25 फ़सल वर्ष के लिए कृषि उत्पादन का जो तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, इस अनुमान के मुताबिक देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन 35.39 करोड़ टन होगा। इसके साथ ही गेहूं, धान, मक्का, मूंगफ़ली और सोयाबीन सहित प्रमुख फ़सलों के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि अनुमानित है। गेहूं का उत्पादन 11.75 करोड़ टन, धान का उत्पादन 14.90 करोड़ टन, मक्का उत्पादन 4.23 करोड़ टन, मोटे अनाजों का उत्पादन 62.1 लाख टन, दलहन उत्पादन 2.52 करोड़ टन, तिलहन उत्पादन 4.26 करोड़ टन, मूंगफ़ली का उत्पादन 1.19 करोड़ टन और सोयाबीन का उत्पादन 1.52 करोड़ टन होने का अनुमान है। भारत मौसम विभाग ने इस साल 2025 में देश में मॉनसून के दौरान औसत से 5 फ़ीसदी अधिक वर्षा के अनुमान प्रस्तुत किए हैं और मानसून ने समय पूर्व दस्तक भी दे दी है। ऐसे में सस्ते कर्ज के बीच अच्छी फ़सल और अच्छे मानसून से सरकार को महंगाई नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-2026 में खुदरा महंगाई के 4 प्रतिशत से नीचे 3.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

निश्चित रूप से नए मौद्रिक उपायों से न सिर्फनकदी में सुधार होगा, बल्कि बैंकों को फंड की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी। सीआरआर में कटौती से दिसंबर 2025 तक बैंकिंग व्यवस्था में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की प्राथमिक नकदी आएगी। ऐतिहासिक रूप से सामान्य समय में सीआरआर 4 प्रतिशत के सामान्य स्तर पर रखा जाता है। अत्यधिक आवश्यक होने पर कोविड-19 महामारी के दौरान सीआरआर घटाकर 3 प्रतिशत के स्तर पर रखा गया था। ब्याज दर घटने से उद्योग-कारोबार के लिए विकास के मौकों के साथ आम आदमी को सस्ते कर्ज के लाभ होंगे। घरों और वाहनों की मांग बढ़ेगी। खास तौर से हाल ही में मकानों की बिक्री में तेज गिरावट के कारण रियल एस्टेट उद्योग की मुश्किलें ब्याज दरों में कटौती से कम होते हुए दिखाई देंगी। ईएमआई के घटने से ऋण लेने वाले सभी लोगों को लाभ मिलते हुए दिखाई देगें। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि ब्याज दर घटने से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बढने में भी मदद मिलेगी। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 जीडीपी में उम्मीद से कम 6.5 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है। अब चालू वित्त वर्ष में सस्ते कर्ज से आर्थिक गतिविधियों में तेजी की संभावना विकास दर को बढ़ाने वाला सकारात्मक संदेश है। ग्रामीण मांग के साथ-साथ शहरी मांग में सुधार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के विकास को बल मिलेगा। सस्ते कर्ज से कई और लाभ मिल सकते हैं। इस समय जब भारत ट्रंप टैरिफ और वैश्विक व्यापार अनिश्चितता के दौर में चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तब सस्ता कर्ज उद्योग-कारोबार को नई शक्ति देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति को मजबूत बनाने, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को व्यापक आर्थिक विवेक से प्रबंधित करने, उद्यमियों को नीतिगत स्थिरता, नवाचार एवं वृहद आर्थिक नीति उपलब्ध कराने के मद्देनजर सस्ता कर्ज लाभप्रद है। सस्ते कर्ज के कारण विदेशी निवेश बढ़ेंगे। इस वर्ष ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौतों के मद्देनजर देश के उद्योग-कारोबार क्षेत्र को सस्ते कर्ज से विकास के मौके बढ़ेंगे। खास तौर से ब्याज दर घटने से विकास के चार इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऐसे में सस्ते कर्ज के आधार पर भारत चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 फ़ीसदी विकास दर को प्राप्त करने वाले देश के रूप में एक बार फिर दुनिया में रेखांकित होते हुए दिखाई देगा। इतना ही नहीं, ब्याज दर घटने से इसी वर्ष 2025 तक भारत की आर्थिकी के चौथी बड़ी आर्थिकी बनने की पूर्ण संभावनाएं साकार होते हुए दिखाई देंगी।

युवाओं में नशे के प्रति बढ़ता आकर्षण गंभीर चुनौती

प्रो. (डॉ.) राजेंद्र प्र. गुप्ता

युवाओं में नशे के प्रति बढ़ता आकर्षण पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती के रूप में सीना तानकर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी 'विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2024' के अनुसार 29.2 करोड़ से भी अधिक लोग पूरे विश्व में मादक पदार्थ के सेवन में लिप्त हैं।

आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या में पिछले दशक की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। नशे के प्रति इतनी रु झान मानव सभ्यता के सामने एक गंभीर संकट की ओर संकेत कर रही है।

भारत में भी युवा बड़ी संख्या में नशाखोरी की चपेट में हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने युवाओं में नशे के प्रति बढ़ती रु चि को एक पीढ़ीगत संकट बताया है। यह चुनौती इतनी गंभीर है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' के तीसरे एपिसोड में 14 दिसम्बर 2014 को पूरी संवेदना के साथ देश के युवाओं से नशाखोरी से बाहर आने की विशेष अपील की थी। साथ ही उन्होंने युवाओं को विास दिलाया कि राष्ट्र के सामने मौजूद इस गंभीर संकट से निपटने के लिए वे युवा वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आंकड़ों के मुताबिक, देश के लगभग 20 प्रतिशत लोग नशे की चपेट में हैं।

इनमें 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। 10 वर्ष से 17 वर्ष की आयु वर्ग वाले लगभग 1.5 करोड़ किशोर भी इस खतरे की चपेट में हैं, जिनमें चिंताजनक संख्या में छोटी-छोटी बेटियां भी हैं। 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडीज 2017' के अनुसार पूरी दुनिया में 7.30 लाख लोग अवैध ड्रग्स के सेवन के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए, जिसमें से 22 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु भारत में भी हुई। एन.सी.आर.बी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ही पूरे देश भर में ड्रग्स से परेशान होकर लगभग 7800 से अधिक लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिसमें 20 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वर्ग वाले अधिक लोग रहे। कष्टदायक स्थिति ये है कि हमारे कुछ युवा नशे के दुष्प्रभाव के कारण मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं।

देश के लगभग 45 मानिसक स्वास्थ्य से जुड़े अस्पतालों में पिछले 10 वर्षों में भर्ती लोगों में 20 प्रतिशत नशे के कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ माने गए। नशे के कारण मानसिक बीमारी के शिकार लोगों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में नशे से संबंधित एफ.आई.आर की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में 3 करोड़ से अधिक लोग भांग के नशे में लिप्त हैं, जिनमें से 72 लाख से अधिक लोग इसकी वजह से अस्वस्थ हैं। 10 लाख के आसपास लोग इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स लेते हैं, जबकि 10 करोड़ से अधिक लोग अनेक अवैध नशीले पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही इस संकट से जूझ रहा है।

अमेरिका, फ्रांस इत्यादि देशों के साथ सीरिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, रूस, ब्राजील इत्यादि देश भी इस समस्या से ग्रसित हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण दुनिया में सबसे अधिक मौतें अमेरिका और फ्रांस में ही हुई हैं। सीरिया में तो सरकार ने ही नशीली दवाओं के व्यापार को वित्त पोषित किया है। विश्व ड्रग रिपोर्ट 2017 के अनुसार केवल अमेरिका में ही नशीली दवाओं के कारण 70 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। सबसे बडी चिंता का विषय यह है कि भारत की शिक्षण संस्थाओं के आसपास चाय-नाश्ते की दुकानों, जनरल स्टोर्स इत्यादि के माध्यम से युवाओं को ड्रग्स और अन्य नशीले पदाथरे के दलदल में घसीटा जा रहा है।

भारत सरकार की ओर से समय-समय पर अनेक आवश्यक कदम उठाए जाते रहे हैं। एक तरफ सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से ड्रग्स के अवैध व्यापार पर लगातार छापेमारी करके उन नशीले पदाथरे को नष्ट कर रही है तो दूसरी ओर इसमें लाभ कमाने की दृष्टि से जो असामाजिक तत्व लगे हुए हैं, उनको कानून के कड़े प्रावधानों के द्वारा दंडित भी कर रही है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नशाखोरी को समाप्त करने के लिए 'ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद से ही ड्रग्स माफिया पर लगातार प्रहार हो रहे हैं।

गृह मंत्रालय की सूचना के अनुसार देश की तमाम जांच एजेंसियों ने हाल ही में 2023 में 16 हजार करोड़ रु पये से भी अधिक का ड्रग्स जब्त किया था। 2024 में 25 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का ड्रग्स जब्त किया गया। 2023 की तुलना में 2024 में 55 प्रतिशत अधिक ड्रग्स जब्त किया गया। अगर हम नशे की गंभीर चुनौती को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें सरकार के प्रयासों को जन भागीदारी से जोड़कर उचित क्रियान्वयन में सहयोग करना होगा। आवश्यकता है विश्व के अग्रणी देशों में नशे की रोकथाम के लिए अमल में लाई जा रही कानून-व्यवस्था के अध्ययन की। इसके आधार पर भारत में नशे की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से अनुसंधान कर उपलब्ध प्रावधानों का आवश्यक संशोधन किया जा सके।

संक्षिप्त समाचार

महापौर अलका बाघमार ने मुख्यमंत्री व नगरीय निकाय मंत्री के प्रति किया आभार व्यक्त

दुर्ग/ समय दर्शन। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर के चहुँमुखी विकास को नई गति प्रदान करने राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है।महापौर अलका बाघमार की दूरदर्शी सोच और सतत प्रयासों के फलस्वरूप दुर्ग को 2 नई फोरलेन सड़कों के साथ ही एक अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग ज़ोन मिलने जा रहा है। साथ ही सिकोला नाला की वर्षों पुरानी मांग भी अब पूरी होगी। इन कार्यों की स्वीकृति से दुर्ग विकास के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करेगा। कुल ?38.95 करोड़ की राशि 5 प्रमुख विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है। महापौर के द्वारा निरंतर वार्डो का दौरा कर जनता की मांगों के अनुरूप विकास कार्यों को पूरा करने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। शहर दुर्ग की जनता को सुविधा और सहूलियत देने के उद्देश्य से की गई मांग के तहत उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए, नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर पालिक निगम दुर्ग को मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद एवं सेंट्रल लाइब्रेरी योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

महापौर अलका बाघमार ने बताया कि स्वीकृत बजट के अंतर्गत: अधोसंरचना मद से साइंस कॉलेज के पास जी.ई. रोड से स्टेशन रोड तक फोरलेन निर्माण हेतु ?5.50 करोड़, सिकोला नाला निर्माण हेतु ?3.00 करोड़, नगरोत्थान मद से स्टेशन रोड से शहीद चौक तक 800 मीटर फोरलेन सड़क हेतु ?9.75 करोड़, राजेन्द्र पार्क चौक से शहीद चौक होते हुए आईएमए चौक तक चौड़ीकरण एवं फोरलेन निर्माण हेतु ?9.27 करोड़, तथा 500 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग ज़ोन परिसर निर्माण हेतु ?11.42 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।इस प्रकार कुल ?38.95 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

विकास कार्य अधोसंरचना की नींव है- महापौर : महापौर श्रीमती बाघमार ने कहा कि यह स्वीकृति केवल एक विकास कार्य नहीं, बल्कि दुर्ग की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत अधोसंरचना की नींव है। शिक्षा, यातायात और नगरीय व्यवस्था के क्षेत्र में यह पहल दुर्ग को प्रदेश के अग्रणी शहरों में स्थान दिलाएगी।

महापौर अलका बाघमार ने मंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त किया : महापौर अलका बाघमार ने शासन से ?38 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव का दुर्ग की जनता और पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आभार जताते हुए कहा कि दुर्ग अब तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। साथ ही महापौर ने कहा कि यह स्वीकृति दुर्ग शहर के विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आयुक्त ने निर्माणाधीन 3000 किलो लीटर उच्चस्तरीय क्षमता वाले जलागार का किया निरीक्षण

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन क्रमांक 03 मदर टेरेसा नगर का निरीक्षण करने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय जोन आयुक्त येशा लहरे के साथ पहुंचे। वार्ड क्रं. 36 महात्मा गांधी नगर में निर्माणाधीन 3000 किलो लीटर उच्च स्तरीय क्षमता वाले जलागार का कार्य प्रगति पर है। जिसके निर्माण की गुणवत्ता और कार्य की स्थिति का अवलोकन करते हुए कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल से जानकारी प्राप्त किये। नया जलागार निर्माण से उस क्षेत्र के लगभग 1500 परिवारों को जल आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में किया जा सकेगा। वहीं सर्कुलर मार्केट में निर्मित सी.सी. रोड का निरीक्षण किया गया है, शेष आवश्यक एवं अन्य जर्जर मार्गो का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने हेतु जोन आयुक्त को निर्देश दिया गया है। शौचालय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसका निरीक्षण आयुक्त द्वारा किया गया है। शौचालय के निर्माण से स्थानीय नागरिको को बड़ी सुविधा मिलेगी। पानी टंकी के समीपस्थ बाल उद्यान का अवलोकन कर घॉस कटिंग एवं वृक्षारोपण कराने उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू को निर्देशित किए। निरीक्षण के दौरान पार्षद विनोद चेलक, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, जोन स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत मांझी, स्वक्षता निरीक्षक चूड़ा मनी यादव, श्याम ठाकुर एवं समाज सेवी त्रिलोचन उपस्थित रहे।

''गौ सेवा संकल्प अभियान'' : जिले में गायों की सेवा, सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने चलेगा अभियान

कलेक्टर ने की आमजनों से सहभागिता की अपील

मुंगेली (समय दर्शन) जिला प्रशासन द्वारा गायों की सेवा एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ''गौ सेवा संकल्प अभियान'' की शुरूआत की गई है। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने औपचारिक रूप से इस अभियान की शुरूआत करते हुए आमजनों से गायों को बचाने, गायों की सेवा, सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सहभागिता की अपील की। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने गौ सेवा संकल्प अभियान के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि गाय माता के समान है, उसके प्रति सम्मान का भाव जागृत करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने लोगों को गाय को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कलेक्टर ने कहा कि इस विशेष पहल के अंतर्गत परित्यक्त एवं बेसहारा गायों के लिए चारा, पानी, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के ठोस प्रयास किए जाएंगे। जिला प्रशासन, नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों और पशु चिकित्सा विभाग के समन्वय से यह अभियान चरणबद्ध रूप से संचालित किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने गाय के प्रति करुणा एवं जागरूकता फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गौवंश के सड़क पर होने से दुर्घटना की आशंका रहती है। सड़क से गायों को हटाएं और इसके लिए लोगों को जागरूक करें, ताकि सड़क दुर्घटना कम हो। उन्होंने सेवा भावना का दृष्टिकोण विकसित करते हुए गायों की सुरक्षा के लिए ईमानदार प्रयास करने और इस पहल को जनभागीदारी तथा जनअभियान के रूप में लेने व गॉवों में चौपाल लगाकर गौ सेवा के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने प्रोत्साहित किया। उन्होंने ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम और रैलियां आयोजित करने तथा युवाओं, स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों और विद्यालयों की भागीदारी सुनिश्चित करने कहा।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गाय का पर्यावरणीय, धार्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व है, गाय हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने अभियान के महत्व बताते हुए कहा कि इसे मिशन के रूप में ले और संवेदनशीलता से गौ सेवा करें। वनमंडलाधिकारी अभिनव कुमार ने कहा कि गौ सेवा न केवल हमारी परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। इस अभियान में समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है, तभी इसका उद्देश्य सफल हो सकेगा। जिला पंचायत सीईओ ने गौ सेवा संकल्प अभियान के कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि बेसहारा गायों को आश्रय प्रदान करना और उनकी देखभाल करना सबसे बड़ी सेवा है। इस मुहिम में हम सभी को शामिल होना चाहिए। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, अपर कलेक्टर जी. एल. यादव एवं श्रीमती मेनका प्रधान, मुंगेली एसडीएम श्रीमती पार्वती पटेल, पथरिया एसडीएम अजय शतरंज सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

आशा की किरण बनी ''चिरायु योजना'', तामेश्वरी की आंख का हुआ सफल ऑपरेशन

कलेक्टर ने प्रदान किया स्कूल बैग, रैन कोट सहित पाठ्य सामाग्री

मुंगेली(समय दर्शन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) के अंतर्गत रायपुर स्थित मेकाहारा अस्पताल में कु. तामेश्वरी साहू की ऑख का सफल आपरेशन किया गया। योजना के तहत आर्टिफिशियल ऑख भी प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट में तामेश्वरी को स्कूल बैग, रैन कोट, टिफिन व पानी बॉटल सहित पाठ्य सामाग्री प्रदान कर शिक्षा की दिशा में वापस लौटने व मन लगाकर पढ़ाई करने और आगे बढ़ने प्रोत्साहित किया। उन्होंने तामेश्वरी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

समग्र शिक्षा अभियान पथरिया बीआरपी श्रीमती प्रिया यादव ने बताया कि एक छोटी सी घटना ने तामेश्वरी की आंखों से रोशनी छीन ली थी, किताब में कव्हर लगाने को लेकर तामेश्वरी का अपनी बहन के साथ कैंची को खींचातानी हुई, जिसमें तामेश्वरी की आंख में कैंची लगने से चोट आ गई। उन्होंने तामेश्वरी की स्थिति से चिरायु टीम की डॉ. ज्योति पाण्डेय को अवगत कराया। टीम द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पथरिया में जांच कराया गया, जिसके पश्चात चिकित्सकों द्वारा तामेश्वरी को जिला चिकित्सालय रामगढ़ रिफर किया गया और वहां से मेकाहारा रायपुर रिफर किया गया, जहां ईलाज और आपरेशन के बाद तामेश्वरी अब बिल्कुल स्वस्थ है।

ग्राम पंचायत चिरपोटी में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिए

500 से अधिक पौधे रोपे गए, जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने लिया उत्साहपूर्वक भाग और पौधे के देखभाल के लिए संकल्प लिए

दुर्ग (समय दर्शन)। ग्राम पंचायत चिरपोटी में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों में कुल 500 पौधे रोपे गए, जिनमें फलदार और छायादार वृक्ष शामिल हैं। कार्यक्रम की अगुवाई ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती पूजा चंद्राकर एवं सचिव सी.एल. साहू द्वारा की गई। सरपंच श्रीमती पूजा चंद्राकर ने कहा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम बढ़ाना है और जनमानस में जागरूकता अभियान को गति देने का है इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित क्षेत्र के जनपद सदस्य ढालेश साहू ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

जनपद सदस्य ढालेश साहू ने अपने उद्बोधन में कहा पौधारोपण केवल एक कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण देने की जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखरेख करनी चाहिए।

कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि उपसरपंच सुरेश कुमार निषाद, एवं पंचगण योगेन्द्र साहू, कौशल साहू, ताराचंद निषाद, परमानंद साहू, श्रीमती राधाबाई देशलहरे, श्रीमती मंजू साहू, श्रीमती हेमबती साहू, श्रीमती पूजा साहू, देवकुमार निषाद सहित ग्राम के कई वरिष्ठ समाजसेवी अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।इसके साथ ही पंचायत सहायक स्टाफ ङ्क श्रीमती कोमलेश्वरी साहू (कंप्यूटर ऑपरेटर), आरएसयू, एलएम शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेट, तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों और ग्रामवासियों को दो-दो पौधे वितरित किए गए और उन्हें अपने-अपने घरों, खेतों तथा सार्वजनिक स्थलों में रोपित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। सभी प्रतिभागियों ने पौधों की सुरक्षा और संरक्षण का संकल्प भी लिया।

सभी प्रकार से पौधों का वितरण व लगाए गए जिसमें जामुन, 130 नग अमरूद,120 नग करौंदा, 70 नग कटहल, 50 नग आंवला, 40 नग आम, 50 नग करंज ,40 नग कार्यक्रम समापन के समय ग्रामवासियों ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों में सहभागिता देने की इच्छा जताई।

उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु आवेदन 31 जुलाई तक

मुंगेली(समय दर्शन) जिल के किसान अपनी उद्यानिकी फसलों जैसे टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक आदि के बीमा के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कम्पनी, भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इच्छुक कृषकों को अधिसूचित फसलों की बीमित राशि का 05 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर देना होगा। इस हेतु बीमा कम्पनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि विशाल गुलाटी मोबाईल नम्बर 7224991180 एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि ताराचंद मोबाईल नम्बर 9617739731 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

अधिसूचित फसलों में टमाटर के लिए देय प्रीमियम 06 हजार रूपए, बैगन के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 03 हजार 850 रूपए, अमरूद के लिए 02 हजार 250 रूपए, केला के लिए 08 हजार 250 रूपए, पपीता के लिए 06 हजार 250 रूपए, मिर्च के लिए 04 हजार 500 रूपए और अदरक के लिए 07 हजार 500 रूपए किसानों को देना होगा। इस योजना में अऋणी कृषक को शामिल होने के लिए घोषणा पत्र के साथ फसल बोआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह ऋणी कृषक, जो योजना में शामिल होना नहीं चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्र अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अनुसार बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस के पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

नियत समय में स्कूल नहीं पहुंच रहा प्रधान पाठक

विकासखंड जैजैपुर के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला करही का मामला

बिर्रा (समय दर्शन)। शिक्षा विभाग के नया समय सारणी के अनुसार प्रत्येक स्कूलों में शिक्षकों को 9:45 बजे स्कूल पहुंचना है और स्कूल में उपस्थित बच्चों को प्रार्थना कराना है। इसके बाद 10:00 बजे से पढ़ाई का शुभारंभ करना है। लेकिन शासकीय प्राथमिक शाला करही में यहां के प्रधान पाठक रमेश कुमार शुक्ला 10:30 बजे स्कूल पहुंच रहा है।

गौरतलब है कि नवीन जिला सक्ती के विकासखंड जैजैपुर के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला करही में कुल दो स्टाफ पदस्थ है। लेकिन 16 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 10:00 बजे स्कूल का जायजा लेने पहुंचे तो यहां पर एक शिक्षिका ममता बाई बंजारे और सफाई कर्मचारी टीकाराम बघेल के अलावा स्कूल में 30 बच्चे उपस्थित मिले। यहां पर पहली से लेकर पांचवी तक की पांच कक्षाएं संचालित है। जिसमें से कुल दर्ज संख्या 34 बताया गया है। 10:30 तक यहां के प्रधान पाठक रमेश कुमार शुक्ला स्कूल नहीं पहुंचा था। प्रत्येक दिन यहां पर पदस्थ प्रधान पाठक रमेश कुमार शुक्ला 10:30 बजे के बाद ही रोजाना स्कूल पहुंचता है। प्रधान पाठक प्रत्येक दिन हमेशा देरी से स्कूल आते हैं, और इसके साथ ही स्कूल से जल्दी घर चले जाते हैं। जिसकी शिकायत के बाद भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री विजय सिदार के द्वारा कार्यवाही नहीं किया

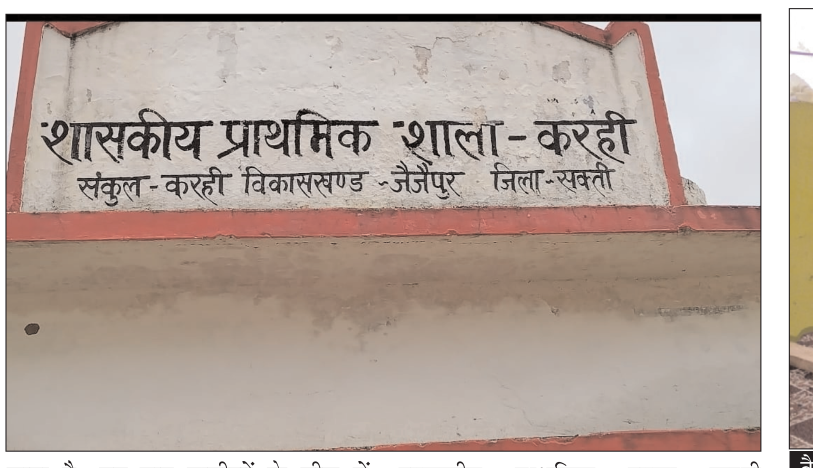

जाता है। यह बात ग्रामीणों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षकों के मनमानी के कारण आजकल शिक्षा विभाग पूरी तरह से कलंकित हो गई है। प्रधान पाठक रमेश कुमार शुक्ला की मनमानी एवं तेवर चरम सीमा के सातवें आसमान पर है। शुक्ला अपने द्वारा बनाए समय सारणी पर स्कूल आता जाता है। इसके बावजूद भी समय से पहले जल्दी घर चला जाता है। यह बात विकासखंड शिक्षा अधिकारी जैजैपुर विजय सिदार के अलावा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की घोर लापरवाही और मिलीभगत कर आपसी सहमति को उजागर करता है।

बहरहाल कारण चाहे जो भी हो शासकीय प्राथमिक शाला करही विकासखंड जैजैपुर के प्रधान पाठक रमेश कुमार शुक्ला का यहां पर अपना बनाया हुआ समय सारणी के अनुसार आना-जाना करना और शिक्षा विभाग के बनाए नियम व समय सारणी पर स्कूल नहीं आना एवं समय से पहले घर जाना यह सभी बातें शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की कमजोरी को दर्शाता है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी जैजैपुर विजय सिदार का पूरा-पूरा सहयोग प्रधान पाठक रमेश कुमार शुक्ला को मिल रहा है। प्रधान पाठक के क्रियाकलाप से परेशान होकर यहां के ग्रामीणों ने उक्त प्रधान पाठक रमेश कुमार शुक्ला को यहां से हटाने की मांग किए हैं।

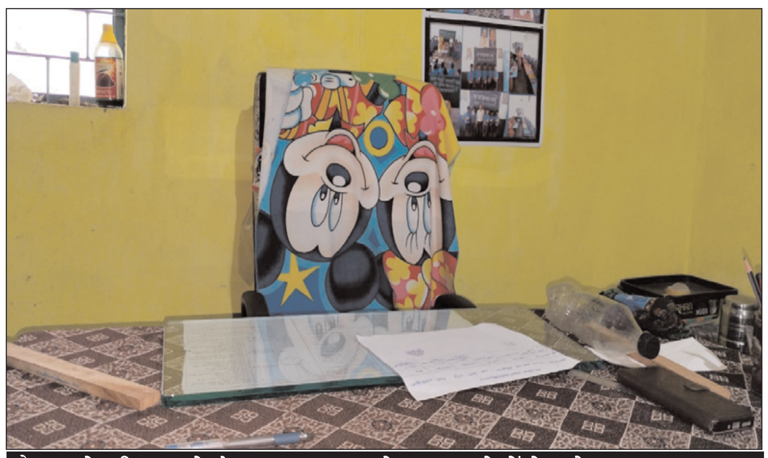

बैनर फ्लेक्सी बनवाने के कारण आज मुझे स्कूल आने में देर हो गया

रमेश कुमार शुक्ला
प्रधान पाठक
शासकीय नवीन प्राथमिक शाला, करही

उचित कार्रवाई करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया जाएगा।

विजय सिदार
विकासखंड शिक्षा अधिकारी
जैजैपुर

शिक्षा विभाग से जारी हुए समय सारणी में स्कूल आना एवं स्कूल से घर जाना है। अगर इसके विपरीत कोई भी शिक्षक या प्रधान पाठक आता जाता है तो उनके खिलाफ जानकारी लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डॉक्टर श्रीमती कुमुदिनी बाग द्विवेदी

जिला शिक्षा अधिकारी
नवीन जिला सक्ती

संक्षिप्त समाचार

कृषि विभाग के उड़नदस्ता टीम द्वारा जिले के विभिन्न उर्वरक विक्रय केन्द्रों का किया गया औचक निरीक्षण

जांजगीर-चांपा (समय दर्शन)। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले के कृषकों को सुगमता पूर्वक गुणवत्तायुक्त कृषि आदान (बीज उर्वरक कीटनाशक) उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय उड़दस्ता दल द्वारा जिले के विभिन्न उर्वरक विक्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। उप संचालक कृषि श्री एल एम भगत ने बताया कि जिला स्तरीय उड़दस्ता दल द्वारा विकासखंड बम्हनीडीह के मेसर्स अग्रवाल कृषि केन्द्र बम्हनीडीह, मेसर्स आनंत ट्रेडर्स बम्हनीडीह, मेसर्स एग्रो सर्विस सेंटर चांपा, मेसर्स सिद्धी कृषि केन्द्र सिवनी, मेसर्स साहू खाद भण्डार सिवनी एवं मेसर्स राठौर खाद भण्डार सिवनी चांपा के उर्वरक विक्रय स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स अग्रवाल कृषि केन्द्र बम्हनीडीह के विक्रय स्थल में भण्डारित उर्वरक प्राप्ति का स्त्रोत नही होने के कारण यूरिया 188 बोरी, एस.एस.पी. 147 बोरी, डी.ए.पी. 52 बोरी, एन.पी.के. 102 बोरी जप्ती की कार्यवाही की गई। मेसर्स आनंत टेऊ्डर्स बिना स्त्रोत के उर्वरक प्राप्ति के चलते सिंगल सूपर फास्फेट 45 बोरी जप्ती की कार्यवाही करते हुए संबंधित को सुपुर्द किया गया। मेसर्स एग्रो सर्विस सेंटर चांपा में लाइसेंस में दर्शित नक्शा अन्यत्र स्थल का होने के कारण गोदाम को सील बंद की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार मेसर्स सिद्धी कृषि केन्द्र सिवनी, मेसर्स साहू खाद भण्डार सिवनी, मेसर्स राठौर खाद भण्डार सिवनी चांपा विभिन्न प्रकार के अनिमियतता के चलते कारण बताओ नोटिस एवं मेसर्स साहू कृषि केन्द्र में बिना स्त्रोत के यूरिया 130 बोरी रखने पर जप्ती करते हुए संबंधित को सुपुर्द किया गया। निरीक्षण के दौरान सहायक संचालक कृषि श्रीमती नीलम आजाद, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी श्री मनीष कुमार मरकाम, निरीक्षक श्री शिव कुमार राठौर, निरीक्षक श्री एन.के.दिनकर एवं श्री रवि साहू उपस्थित रहे।

सहायता समूहों के बैंक लिंकेज हेतु बैंकर प्रशिक्षण सह कार्यशाला सम्पन्न

जांजगीर-चांपा (समय दर्शन)। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के बैंक क्रेडिट लिंकेज को सशक्त करने, मिशन की मूल अवधारणाओं, ऑनलाइन ऋण आवेदन प्रक्रिया तथा आरबीआई मास्टर सर्कुलर की समग्र जानकारी प्रदान करने हेतु आज जिला पंचायत के सभा कक्ष में बैंकर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में श्रीमती नियति ध्रुवे एवं एन आर पी श्री गगन बिहारी भुईयाँ, एलडीएम श्री नरोत्तम साहू, जिला मिशन प्रबंधक श्री उपेन्द्र कुमार, समस्त बैंक शाखाओं के शाखा प्रबंधक, विकासखंड प्रभारी, एफएलसीआरपी, बैंक मित्र, बैंक सखी तथा बिहान टीम के सदस्य उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में बैंकरों को स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ने की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, ऋण स्वीकृति एवं वितरण, दस्तावेजीकरण तथा आरबीआई के मास्टर सर्कुलर की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में पीपीटी के माध्यम से बताया गया कि बैंकर्स की सक्रिय भागीदारी और सहयोग से महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक स्थिति में सशक्त सुधार संभव है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह प्रशिक्षण कार्यशाला बैंकों एवं स्व-सहायता समूहों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विधायक चातुरी नंद ने प्रदेश में शक्ति चलित कृषि यंत्रों व उपकरणों के वितरण हेतु लागू चैंप्स व्यवस्था में अनियमितता का मामला विधानसभा में उठाया

- ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से कृषि मंत्री से पूछे तीखे सवाल
- किसानों को सीधे ऑनलाइन पंजीयन नहीं होने से ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र मिलने में आ रही दिक्कतों से कराया मंत्री को अवगत

सरायपाली नृपनिधी पाण्डेय (समय दर्शन)। विधायक चातुरी नंद ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन प्रदेश में शक्ति चलित कृषि यंत्रों व उपकरणों के वितरण हेतु लागू चैंप्स व्यवस्था में अनियमितता मामले का कृषि मंत्री रामविचार नेताम का ध्यानाकर्षण कराया।

विधायक चातुरी नंद के ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अपने लिखित व्यक्तव्य में बताया कि प्रदेश के शक्ति चलित कृषि यंत्रो, सिंचाई पंपो, ड्रिप/स्प्रिंकलर के वितरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी आधारित चैम्प्स व्यवस्था वर्ष 2017-18 से संचालित है, १यह व्यवस्था प्रदेश में कृषि एवं उद्यानिकी ने यांत्रिकीकरण हेतु संचालित सभी केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाओ में यंत्रो के प्रदाय की व्यवस्था है। दिनांक 14 मई 2025 को चैम्प्स पोर्टल खोलने के संबंध में पत्र कमांक मुख्या/बी.कृ.वि.नि./चैम्प्स/2025-26/31 दिनांक 13.05.2025 द्वारा समस्त पंजीकृत प्रदायको को सूचना दी गई है पोर्टल शाम कार्यालयीन समय के बाद प्रारंभ होने का प्रमुख कारण चैम्प्स पोर्टल के सिक्योरिटी ऑडिट नहीं होने के कारण चिप्स के द्वारा उसे तत्काल बंद कर दिया गया था। चैम्प्स प्रकोष्ठ प्रभारी द्वारा चिप्स से संपर्क एवं पत्राचार उपरांत पोर्टल दिनांक 14 मई 2025 को सायं 5 बजकर 55 मिनट पर प्रारंभ हुआ। पोर्टल प्रारंभ होने के पश्चात् सर्वर में समस्या (अधिक लोड) होने के कारण पोर्टल धीमे कार्य कर रहा था तथा कभी-कभी एरर भी प्रदर्शित कर रहा था। अतः पोर्टल पुनः 7.30 बजे खोले जाने संबंधी कथन सही नही है अपितु पोर्टल सायं 5.55 बजे प्रारंभ होने के पश्चात् निरंतर खुला रहा।

कृषि मंत्री ने अपने लिखित जवाब में यह भी बताया कि पोर्टल प्रारंभ होने के पश्चात् समस्या, केवल 02 ट्रेक्टर सोनालिका एवं महिन्द्रा द्वारा अधिकतम ऑनलाईन एन्ट्री की गई जबकि अन्य कंपनियों को पोर्टल में एन्ट्री करने के संबंध में पोर्टल से संबंधित विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जांच हेतु सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से जांच कराया जाना प्रक्रियाधीन है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-

दोष के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

मंत्री के जवाब में यह बात भी सामने आई कि टैफे ट्रेक्टर कंपनी के अधिकृत प्रदायक मेसर्स रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर द्वारा दिनांक 14.05.2025 को समय रात्रि 8.32 बजे ई मेल द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें पोर्टल में कृषको के आवेदन की प्रविष्टि में समस्या आ रहीं है जबकि एक कंपनी के ही आवेदन पंजीकृत हो रहे है। पोर्टल के अवलोकन पर पाया गया कि 09 पंजीकृत प्रदायको द्वारा 206 आवेदन पोर्टल में पंजीकृत कराये गये है। चैम्प्स पोर्टल में पंजीकृत प्रदायको को लॉगिन पासवर्ड की सुविधा के साथ-साथ सभी इच्छुक कृषक जो चैम्प्स में सम्मिलित योजना का लाभ लेना चाहते है वे पोर्टल में सीधे पंजीयन करा सकते है। वर्ष 2024-25 में 506 एवं 2025-26 में अब तक 1763 किसानों द्वारा चैम्प्स पोर्टल में कृषि यंत्रो की प्राप्ति हेतु सीधे आवेदन प्रस्तुत किया गया है। चैम्प्स पोर्टल में एक ही लॉगिन पासवर्ड का उपयोग कर विभिन्न कम्प्युटर सिस्टम, लेपटॉप आदि में उपयोग किये जाने की सुविधा है। यह सुविधा किसी प्रदायक विशेष के लिये न होकर समान रूप से सभी के लिये है।

कृषि मंत्री के जवाब में यह भी उल्लेखित था कि संचालक कृषि एवं उद्यानिकी द्वारा चैम्प्स में सम्मिलित योजना के लक्ष्य वित्तीय वर्ष के प्रारंभमें जिलेवार जारी किये गये। योजना अंतर्गत बीज निगम मुख्यालय को जिलेवार, वर्गवार प्राप्त आवेदन एवं कृषक अंश के आधार पर भारत सरकार से प्राप्त राशि के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए संचालको को लक्ष्य संशोधन का प्रस्ताव भेजकर संशोधित लक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत स्वीकृति जारी की गई है। दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर जिलो में प्रदायित प्रारंभिक लक्ष्य के विरुद्ध ट्रेक्टर तथा उपकरणो के आवेदन एवं कृषक अंश राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त लक्ष्य को अन्य जिलो में जहां वर्गवार अधिक प्रकरण पंजीकृत होने के साथ साथ कृषक अंश राशि भी जमा कराया गया है, उन जिलो को लक्ष्यो का पुर्नविभाजन करते हुए संशोधित लक्ष्य जारी किये जाते है। वर्ष 2024-25 में दंतेवाड़ा जिले में कुल 27 (25 ट्रेक्टर), बीजापुर में कुल 22 (17 ट्रेक्टर), सुकमा कुल 18 (14 ट्रेक्टर) एवं नारायणपुर कुल 08 (7) ट्रेक्टर) के आवेदन स्वीकृत कर कृषि यंत्र/उपकरण प्रदाय किये गये है। दिनांक 14 मई 2025 में ऑनलाईन पंजीयन संबंधी प्राप्त शिकायतो के परिपेक्ष्य में त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति के अभिमत/अनुशंसा एवं गुण-दोष के आधार पर व्यवस्था में आवश्यक संशोधन करते हुए इसे और पारदर्शी एवं कृषकोन्मुखी बनाने की कार्यवाही की जाएगी। जिसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाएगा।

विधायक चातुरी नंद ने कृषि मंत्री से सिर्फ एक दो ही ट्रैक्टर कंपनियों को पंजीयन होने पर सवाल उठाया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की जिसको मंत्री ने स्वीकारते हुए पूरे प्रक्रिया की जांच का आश्वासन दिया।

विदित हो कि सरायपाली विधायक चातुरी नंद विधानसभा के मानसून सत्र में लगातार किसानों, युवाओं और महिलाओं की आवाज बुलंद कर रही है। जनहित के मुद्दे उठाने के लिए सरायपाली विधायक चातुरी नंद पूरे प्रदेश में एक विशिष्ट पहचान बना चुकी है।

विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का दानव

- बसना गौरव पथ पूर्ण होने से पहले चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट
- सौंदर्यीकरण और विकास के नाम पर भ्रष्टाचार चरम पर

बसना (समय दर्शन)। बसना नगर पंचायत द्वारा कराये जा रहे लाखों, करोडों के गौरव पथ निर्माण पूर्ण होने से पहले ही उखड़ने और दरारों की भेंट चढ़ चुका है । एक ओर जहां सरकार शहरों के सौंदयीकरण और विकास के नाम पर करोड़ों की योजनाएं चला रही है। वहीं दूसरी ओर बसना नगर का भौरव पथ भ्रष्टाचार की मिसाल बनता जा रहा है। नगर के बाजार चौक से गुरुनानक धर्मशाला तक बनाए गए। सीसी रोड की स्थिति कुछ ही महीनों में जर्जर होने लगी है। निर्माण के तुरंत बाद से ही सड़क पर दरारे और गिट्टियां उखड़ने लगे हैं ।

शिकायत के बाद भी जांच नहीं- स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने 6 माह पूर्व नगर पालिका व जिला प्रशासन को लिखित शिकायत की थी। जिसमें इस सीसी रोड में हो रही अनियमितताओं और गुणवत्ता में भारी कमी की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने समय बाद भी जांच की कोई पहल नहीं की गई है।

अधिकारी-ठेकेदार की सांठगांठ का संकेत- लोगों का कहना है कि जब सड़क पर डिवाइडर बनाए जा रहे थे, उसी दौरान अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर दरारों को सीमेंट से भरकर ढँकने की

कोशिश की थी, ताकि पुराने निर्माण की खामियाँ छुपाई जा सके। यह सीधे-सीधे शासन के पैसे के दुरुपयोग और अधिकारी ठेकेदार की सांठगांठ का संकेत देता है।

निर्माण की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल- गौरव पथ को बनाने में लाखों रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन कुछ ही समय में इसकी हालत खस्ता हो गई है। डिवाइडर बनने के तुरंत बाद सीसी रोड में दरारें दिखना, निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आम नागरिकों का कहना है कि अगर रोड इतनी जल्दी खराब हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

सवाल टैक्स के पैसे का हिसाब कौन देगा- अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या गौरव पथ पर छाए भ्रष्टाचार के साये को हटाया जा सकेगा। फिलहाल, बसना की जनता यह जानना चाहती है कि उनके टैक्स के पैसे का हिसाब

विकास के नाम पर पैसों की बर्बादी है। सरकार से तो हमें उम्मीद थी कि ये गौरव पथ नगर के गौरव को बढ़ाएगा, लेकिन यह तो भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है।

नगर में विकास नहीं, बल्कि पैसों की बर्यादी हो रही है।

जांच को टालने की प्रवृत्ति या ठेकेदार के भ्रष्टाचार मे शामिल- दोनों ही स्थिति प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाते है। नागरिकों को डर है कि कहीं ऐसा न हो कि जब उक्त सड़क की गारंटी अवधि पूरी हो, तब तक जांच न हो और फिर उसी ठेकेदार को मेंटेनेस का कार्य सौंप दिया जाए।

जिम्मेदारों की चुप्पी पर भी उठ रहे सवाल- इस संबंध मे सामाजिक कार्यकर्ता महेन्द्र साव ने बताया कि, पदमपुर रोड गौरव पथ मे प्रतिदिन हजारों लोगों की आगाजाही होती है। हाल ही में बने इस मार्ग में कुछ ही दिनों में दरारें और गिट्टी का उखड़ना भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है । अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति और बदतर हो सकती है। जिम्मेदारों की चुप्पी बसना के विकास को ले डुबेगी।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण,1050 से अधिक बालिकाएं हो रहीं सशक्त

बेमेतरा (समय दर्शन)। परियोजना-बेरला, जिला बेमेतरा में महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब) द्वारा 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को आत्मरक्षा का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह एक माह का प्रशिक्षण शासकीय कन्या शाला बेरला एवं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कुसमी में संचालित हो रहा है, जिसमें अब तक 1050 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। यह प्रशिक्षण दी वॉर काई मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फडिफेंस एकेडमी, बेमेतरा के अनुभवी मास्टर ट्रेनर भानु प्रताप साहू द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में किकबॉक्सिंग, वुशू, कराते, पंच, ब्लॉक, काता, फिजिकल फिटनेस जैसे मार्शल आर्ट्स के साथ-साथ आत्मरक्षा के व्यावहारिक गुर सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण से बालिकाओं में सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, सामाजिक व्यवहार और मोबाइल की लत से मुक्ति जैसे गुणों का भी विकास हो रहा है। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन तथा महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री सी.पी. शर्मा के निर्देशन में यह प्रशिक्षण सत्र संचालित हो रहा है।

जिला मिशन समन्वयक श्री राजीव कुमार वर्मा ने बताया कि मास्टर ट्रेनर भानु प्रताप साहू पिछले 19 वर्षों से मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे 3 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। उन्होंने 17 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और 6 स्वर्ण, 2 रजत एवं 3 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। राज्य स्तर पर उन्होंने 13 स्वर्ण व 1 रजत पदक सहित 16 बार सहभागिता की है। संस्था द्वारा अब तक 643 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, जिनमें से 193 ने स्वर्ण पदक, 167 ने रजत और 143 ने कांस्य पदक अर्जित किए हैं। इससे बालिकाओं को न केवल सुरक्षा के प्रति सजग किया जा रहा है, बल्कि उन्हें सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाया जा रहा है, जिससे वे हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सकें।

विश्व युवा कौशल दिवस में युवाओं को किया गया जागरूक

बसना (समय दर्शन)। मेरा युवा भारत महासमुंद (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार) एवं शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद के संयुक्त तत्वाधान में 15 जुलाई 2025 को विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन किया गया। उद्योग अकादमिक, एकीकरण कौशल/ उद्यमिता एवं रोजगार विकास प्रकोष्ठ व खेल एवं युवा कल्याण विभाग महासमुंद एवं प्राचार्य के निर्देशानुसार विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन किया गया द्ध कार्यक्रम में मुख्य अतिथि करुना दुबे प्राचार्य शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, अध्यक्षता में वसुंधरा साहू मेरा युवा भारत महासमुंद, अतिथि के रूप में अशोक साहू सहायक संचालक कौशल विकास केंद्र महासमुंद, जीतू सिंह तोमर प्रबंधक बैंक ऑफ़ बड़ोदा महासमुंद, समीर चंद्राकर प्रोजेक्ट ऑफिसर अंबुजा फाउंडेशन,उपस्थित रहे द्ध कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता एवं स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया । सभी वक्ताओं का स्वागत बैच लगाकर एवं पुष्प गुच्छ के

द्वारा किया गया। स्वागत उद्बोधन प्राचार्य करूना दुबे के द्वारा किया गया जिन्होंने अपने स्वागत उद्बोधन में पढ़ाई के साथ-साथ स्किल को निखारने और धन अर्जन करना बताया। तत्पश्चात अशोक साहू सहायक संचालक कौशल विकास केंद्र महासमुंद के द्वारा अपना उद्बोधन हुनर है तो कदर है वाक्य से प्रारंभ किया। उन्होंने कहा आज के समय में डिजिटल साक्षरता जरूरी है अगर रोजगार चाहिए तो हर क्षेत्र के लिए हुनर एवं तकनीकी ज्ञान जरूरी है भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं ग्रामीणों के लिए कौशल विकास योजना चलाई जाती है, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लीड बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा युवा स्वरोजगार कर सकते है एवं स्वयं के साथ-साथ दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराते है। तत्पश्चात जीतू सिंह तोमर प्रबंधक बैंक ऑफ़ बड़ौदा महासमुंद के द्वारा लोन संबंधित जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने लोन कौन ले सकता है, किस चीज के लिए लोन दिया जाता है, इन सब की जानकारी दी एवं छात्र-छात्राओं से प्रश्नोत्तरी किया गया, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि लोन लेने से पहले काम सीखना पड़ता है जिससे उस लोन के जरिए इनकम जनरेट हो सके। बैंक लाभ अर्जित करने के लिए लोन देती है उसके बाद ओम प्रकाश पटेल के द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसके बारे में बताया जिसमें उन्होंने कंप्यूटर प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर कोर्स मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इत्यादि प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। तत्पश्चात समीर चंद्राकर प्रोजेक्ट ऑफिसर अंबुजा फाउंडेशन के द्वारा अपने वक्तव्य में युवा कौशल विकास में युवा क्यों जोड़ा गया, कौशल एवं विकास का अर्थ समझाया। स्किल क्यों जरूरी है इसके बारे में बताएं उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा जो दिखता है वही बिकता है उन्होंने अपने फाउंडेशन द्वारा संचालित ष्टस्क्र (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) के अंतर्गत होने वाले प्रशिक्षण को बताया जिसमें इलेक्ट्रीशियन, सहायक नर्सिंग, रिटेलर एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के बारे में बताया। अंत में वसुंधरा साहू जिला युवा अधिकारी के द्वारा अलग-अलग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया एवं नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया महाविद्यालय की ऋतिक पहारिया ने अपना एक्सपीरियंस बताया एवं साहू मैम ने ख्र क्द्धड्डह्ल्ड्डह्ल में स्ष्द्दद्बठ्ठ करने की प्रक्रिया को समझाया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप कन्हेर सहायक प्राध्यापक एवं आभार व्यक्त दिलीप बढ़ाई के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक मालती तिवारी सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, अजय कुमार राजा वाणिज्य, मनबोध चौहान मनीषा प्रधान, मेरा युवा भारत महासमुंद से अशोक चक्रधारी एवं अन्य महाविद्यालय स्टाफ मुख्य वक्ताओं के साथ आए हुए उनके सहायक, एनएसएस, एनसीसी एवं विभिन्न कक्षाओं के छात्र - छात्राएं उपस्थित रहेद्य कार्यक्रम का अंत एक पेड़ मां के नाम योजना के अंतर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य एवं वक्ताओंके द्वारा वृक्षारोपण कर किया गया द्य

खबर-खास

शिव महापुराण में भगवान शिव की बाराती बने श्रद्धालु भक्ति भाव में खूब झूमें

कवर्धा (समय दर्शन)। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी समिति जोराताल में आयोजित शिव महापुराण महाकथा के चौथे दिन वैष्णवाचार्य सुरेन्द्र दास (श्रीधाम वृंदावन) के मुखारबिंदु से शिव कथा की गंगा में सैकड़ों श्रद्धालु भाव-विभोर होकर डुबकी लगाते देखे गए। शिव-पार्वती विवाह प्रसंग में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की बाराती बनकर भक्ति भाव में खूब झूमें।

आचार्य सुरेंद्र दास ने कहा कि भगवान शिव-पार्वती विवाह से हमें भक्ति, धैर्य, और आध्यात्मिक सद्भाव की सीख मिलती है। उन्होने कहा कि शिव महापुराण के अनुसार, यह विवाह शुद्ध प्रेम, आपसी सम्मान, और निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक है। पार्वती की कठोर तपस्या और शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति इस विवाह का महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस विवाह में पार्वती की भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण इस विवाह का मुख्य संदेश है। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे पता चलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह दिव्य शिव महापुराण कथा 13 से 20 जुलाई 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से आयोजित की जा रही है, जिसमें जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर पुण्यलाभ अर्जित कर रहे हैं। साथ ही शिवमहापुराण कथा आयोजन समिति में प्रमुख रूप से कालोनी वासियों के साथ देवी चंद्राकर, संतोष भारद्वाज, शिवा कसार, राजकुमार चंद्रवंशी, प्रवीण परिहार, अमित श्रीवास्तव, नवल नरवरिया, सुभांक श्रीवास्तव, दिवाकर राजपूत, वर्षा चंद्राकर, वंदना श्रीवास्तव, वर्षा ठाकुर, पार्वती चंद्रवंशी एवं राजीव केशरी प्रमुख रूप से शामिल हुए।

गरियाबंद पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव,अभिव्यक्ति ऐप,चेतना यातायात जागरूकता,साइबर फ्रॉड के संबंध में किया गया जागरूक

गरियाबंद।पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों को जागरूक करने हेतु पहल किया जा रहा है। इसी पहल के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर विकास पाटले , उप निरीक्षक ज्ञानेश्वर गंगवाल व थाना मैनपुर टीम द्वारा लगातार मैनपुर क्षेत्र के स्कूल में जाकर बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। किसी कड़ी मे 15 जुलाई को आई.टी.आई.मैनपुर (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) मैनपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र/छात्राओं तथा शिक्षकगणों को नया सवेरा पहल के अंतर्गत नशे के दुष्प्रभाव, अभिव्यक्ति ऐप, चेतना, यातायात जागरूकता,साइबर फ्रॉड, पॉक्सो एक्ट आदि विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

भाजपा सरकार ने डेढ़ साल में चौथी बार बिजली दाम बढाकर जेब में कर रही डकैती

पत्रकार वार्ता

कवर्धा (समय दर्शन)। भाजपा सरकार ने डेढ़ साल में चौथी बार बिजली दाम बढाकर लोगों के जेब में डकैती कर रही है। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट और गैर घरेलू बिजली की दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है। इतना ही नहीं कृषि पंप की बिजली दर सबसे अधिक 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी से किसानों की कमर ही टूट गई है।

कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष होरी चंद्रवंशी एवं महिला अध्यक्ष सीमा अगम अनंत ने उक्त बातें कही। उन्होने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर लूटने का काम भाजपा सरकार ने किया है। यह कोई पहली बार नहीं है। डेढ़ साल के भीतर ही राज्य सरकार चार बार बिजली दर की बढोतरी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के किसान इस सरकार की दुर्भावना और उपेक्षा के चलते पहले ही खाद, बीज और बिजली कटौती से परेशान हैं। अब कृषि पंप में बिजली की दर बढ़ने से किसानों की कमर ही टूट गई है।

इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जनता को लूटने के तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। 2003 से 2018 तक भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने हर साल बिजली के दामों में वृद्धि की। छत्तीसगढ़ में 2003 में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 रुपए 30 पैसे के दर पर बिजली मिलती थी, जिसे 15 साल के कुशासन के बाद रमनसिंह के समय ही 6 रुपए 40 पैसे तक बढ़ाया गया, जिसे चुनाव चुनावी वर्ष 2018 में मात्र 20 पैसे घटकर 6 रुपया 20 पैसे किया गया।

पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में पूरे 5 साल में नेट वृद्धि यदि देखें तो मात्र दो पैसे का था, जो ऐतिहासिक तौर पर सबसे न्यूनतम था। वर्ष 2003-04 में बिजली दर 3.30 रुपए थी, जो 2017-18 में बढ़कर 3.10 रुपए बढ़कर 6.40 हो गई। इस तरह रमन सरकार में कुल वृद्धि 3 रुपए 10 पैसे अर्थात 94 प्रतिशत हुई। वहीं 2018-19 में 6.20, 2019-20 में 5.93 (-27) 2020-21 में 5.93 कोई बढ़त नहीं, 2021-22 में 6.08, 15 पैसे की बढ़त, 2022-23 में 6.22, 12 पैसे की बढ़त, 2023-24 में 6.22 कोई बढ़त नहीं हुई। इस तरह कांग्रेस सरकार के 5 साल में कुल बढोतरी .02 रुपए या दो पैसे या केवल 32 पैसे की बढोतरी हुई है। जबकि भाजपा की वर्तमान सरकार में 7.02 (.80) बढोतरी के साथ जनता परेशान हैं। भाजपा की वर्तमान साय सरकार के डेढ़ साल में कुल वृद्धि 80 पैसे अर्थात 13 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने बिजली के घाटे को पाटते हुए बिजली बिल ऑफयोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 65 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 3240 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर बहुत बड़ी राहत दी थी। किसानों को 5 एचपी तक निशुल्क बिजली दिया, बीपीएल उपभोक्ताओं को 40 यूनिट तक मुक्त बिजली दी गई। अस्पतालों, उद्योगों को रविनी देकर राहत पहुंचाया। भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश भर में बिजली की कटौती शुरू हो गई और कीमत लगातार बढाई जाने लगी है। कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन, हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेचा जा रहा है ?

भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारी एसी का मजा लूट रहे, कई सरकारी विभाग बिजली का बकाया बिल जमा नहीं कर रहें, सरकारी उपक्रमों और सरकार के चहेतों का करोड़ों का बिजली बिल का भुगतान लंबित है, उसकी वसूली भी सरकार जनता से कर रही है।

सत्ता के संरक्षण में बिजली चोरी और लाइन लॉस के मामले बढ़े हैं, जिसके चलते हो रहे नुकसान की भरपाई भी सरकार जनता से वसूली चाहती है।

केंद्र की मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते बिजली का उत्पादन लागत बढा है। कोवल पर ग्रीन टेक्त चार गुना अधिक बहा दिए, रंल का माल माड़ा अधिक वसूल रहे हैं, थर्मल पॉवरप्लांट को अडानी की कंपनी से महंगे दर पर कोयला खरीदने बाध्य किया जा रहा है, डीजल पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ाए जाने से परिवहन में और फायर के लिए उपयोग होने वाले डीजल की लागत बढ़ी है जिसकी भरपाई भी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाकर किया जा रहा है।

स्मार्ट मीटर के नाम पर अधिक बिल की वसूली हो रही- प्रदेश भर से अनाप-शनाप बिजली बिल आने की शिकायत लगातार आ रही है, स्मार्ट मीटर के नाम पर अधिक बिल उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है, अब तो जनता को लूटने के लिए अडानी की कंपनी का प्रीपेड मीटर भी लगाया जा रहा है। अघोषित कटौती रोज-रोज जारी है। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध करती है, सरकार के इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।

गजपल्ला वाटरफॉल बना दर्दनाक हादसे का गवाह – 21 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गुफा से मिला महविश खान का शव

गरियाबंद (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध लेकिन खतरनाक गजपल्ला वाटरफॉल में रविवार को हुआ एक दर्दनाक हादसा, 21 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सोमवार दोपहर 1:45 बजे एक दुखद मोड़ पर खत्म हुआ। रायपुर की रहने वाली 22 वर्षीय महविश खान का शव वाटरफॉल के नीचे गुफा नुमा सुरंग से बरामद किया गया। महविश रविवार शाम करीब 5 बजे अपने दोस्तों—चार युवतियों और दो युवकों के साथ पिकनिक मनाने यहां पहुंची थी, लेकिन अचानक रहस्यमयी ढंग से पानी में डूबकर लापता हो गई। घटना के बाद मौके पर एसडीआरएफ, गरियाबंद पुलिस, वन अमला, और नगर सेना की संयुक्त टीमों ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 23 से ज्यादा जवान जुटे रहे। रेस्क्यू के दौरान यह सामने आया कि वाटरफॉल के नीचे दो गहरे सुरंगनुमा रास्ते हैं, जिनकी गहराई लगभग 30 से 40 फीट है। पानी का बहाव और लगातार बारिश की वजह से सर्च में भारी बाधाएं आईं। एसडीआरएफ के अंडरवाटर कैमरे भी 10 फीट से नीचे जाकर काम करना बंद कर दे रहे थे। गोताखोर भी सुरंग की गहराई में नहीं जा पा रहे थे। मौके पर मधुमक्खियों के झुंड की मौजूदगी ने खतरा और बढ़ा दिया था। स्थानीय प्रशासन ने पहले ही इस स्थान को पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन बावजूद इसके पर्यटक अलग-अलग रास्तों से यहां पहुंच जाते हैं। करीब 80 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई और उतराई की चुनौती भी रेस्क्यू टीम के लिए कठिन बनी रही।

महविश के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवती अचानक पानी के बहाव में खिंच गई और फिर दिखाई नहीं दी। हादसे के बाद से ही पूरा गरियाबंद जिला स्तब्ध है।

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को दिया गया आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

गरियाबंद। महिला सशक्तिकरण केन्द्र महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत कलेक्टर बी.एस.उईके के निर्देशन में एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय के मार्गदर्शन में 7 से 11 जुलाई तक 5 स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इनमें शासकीय हाई स्कूल सढ़ौली,शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीपरछेड़ी, शासकीय कन्या हाई स्कूल मैनपुर,शासकीय हाई स्कूल नहरगांव तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गरियाबंद में ताइक्वांडो मास्टर ट्रेनर किरण मरकाम द्वारा किशोरी बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया।प्रशिक्षण में बालिकाओं को न केवल शारीरिक आत्मरक्षा की तकनीक सिखाई गई। साथ ही उनके आत्मविश्वास को भी मजबूत किया गया।किशोरी बालिकाओं को आत्मरक्षा के विभिन्न व्यावहारिक गुण सिखाए गए।जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में खुद की रक्षा कर सकें और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ सकें।कार्यक्रम के दौरान जिला मिशन समन्वयक मनीषा वर्मा द्वारा बताया गया कि बालिकाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने के लिये यह प्रशिक्षण दिया गया। ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके तथा छात्राओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी योजनाओं एवं लैंगिक समानता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

11 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने खोला मोर्चा

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने बुधवार को अपने पूर्व निर्धारित रुपरेखा के अनुसार प्रांतीय आह्वान पर भोजनावकाश के बाद 11 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त जिला कार्यालय के समक्ष एकत्र होकर नारेबाजी की तथा अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम पर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।फेडरेशन से संबद्ध सभी संघ के पदाधिकारी और सदस्य रैली व ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में कलेक्टर परिसर में उपस्थित हुए।फेडरेशन पदाधिकारियों ने कहा कि यह ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास है इसके उपरांत चरणबद्ध तरीके से 22 अगस्त को एकदिवसीय धरना उसके पश्चात मांग पूरी न होने पर अनिश्चित कालीन हड़ताल फेडरेशन के नेतृत्व में की जाएगी। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर पेंशन प्रकरण के संबंध में चर्चा की तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में समयमान वेतनमान व अन्य समस्याओं के संदर्भ में अधिकारियों से सौजन्य मुलाक़ात कर आवश्यक चर्चा की। वही फेडरेशन प्रदर्शन दौरान मांग रखते हुए बताए कि प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशनरों के लिए केंद्र के समान दो प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए।

समक्ष – श्रीमान पब्लिक नोटरी महोदय जी स/लोहारा जिला कबीरधाम छ.ग.

शपथपत्र

मैं शपथकर्ता विष्ण कुमार डड़सेना पिता अर्जुन डड़सेना उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम स. लोहारा तह स. लोहारा जिला कबीरधाम छ.ग. निम्न कथन शपथ पूर्वक करता हूं-

1. यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार है।
2. यह मेरे पुत्री काव्या डड़सेना के नाम से जारी जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटिवश माता का नाम अंजु बाई दर्ज हो गया है। जबकि अन्य दस्तावेज के अनुसार त्रुटि सुधारकर अंजु डड़सेना किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतएव शपथपत्र प्रस्तुत है।

शपथ कर्ता
विष्णु डड़सेना

सत्यापन

मैं शपथकर्ता सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र में सम्पूर्ण विवरण स्वत: के ज्ञान से सत्य है। अत: आज दिनांक 10-07-2025 हस्ताक्षर/नि.अ. लगाकर निष्पादित किया।

नोटरी सील

शपथ कर्ता
विष्णु डड़सेना
स. लोहारा

कमीशनखोरी की भेंट चढ़ी नगर की सुरक्षा, करंट के खतरे से दहशत में लोग

गरियाबंद (समय दर्शन)। गरियाबंद नगर में भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल अब बरसात में पूरी तरह खुल चुकी है। नगर पालिका की अनदेखी और घटिया निर्माण कार्य के चलते नगर की सड़कों पर चलना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। बरसात के मौसम में पानी भरने के साथ ही नगर के बिजली के खंभे और सड़क किनारे बिछे स्ट्रीट लाइट के तार मौत का फंदा बनते जा रहे हैं।

नगर में पिछले कार्यकाल के दौरान कमीशनखोरी के चलते जगह-जगह सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, लेकिन मानक स्तर की पूरी अनदेखी करते हुए घटिया स्तर का काम कराया गया। महज दो इंच गहराई में तार बिछाकर सीमेंट की एक पतली परत से उसे ढंका गया, जो अब बारिश और यातायात के दबाव से टूट चुका है। नतीजा यह है कि कई जगह तार बाहर निकल आए हैं और कई खंभों में करंट का रिसाव लगातार हो रहा है। स्थानीय लोगों की मानें तो इस करंट लीकेज की वजह से अब तक कई मवेशियों की मौत हो चुकी है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। लोग आशंकित हैं कि यदि यही स्थिति बनी रही तो किसी दिन बड़ी मानवीय दुर्घटना घट सकती है।

बरसात के कारण जगह-जगह जलभराव की स्थिति है और पानी के संपर्क में आते ही खुले और क्षतिग्रस्त तारों में करंट दौड़ने लगता है। राहगीरों के लिए यह मौत का जाल बन गया है। नगर के कई हिस्सों में नागरिकों ने खुद लकड़ी और अन्य साधनों से वायर को सड़क से किनारे किया है।

नगरवासियों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद नगर पालिका आंख मूंदे बैठी है। नगरवासियों की मांग है कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफसख्त कार्रवाई की जाए और पूरे नगर में बिजली व्यवस्था का पुर्ननिरीक्षण कर दुरुस्त किया जाए।

इस मामले को लेकर जब नगर पालिका के सीएमओ संध्या वर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि, मामला संज्ञान में आया है। हमने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देशित किया है कि ऐसी सभी जगहों की पहचान कर मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

न्यायालय नजूल जांच अधिकरी, दुर्ग (छ.ग.)

//ईश्तहार//

20506103800022
रा.प्र.क्र./37/अ-20(1)
वर्ष 2024/25

आवेदक रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय आ.स्व.आर.डी.पाण्डेय, निवासी हुडको भिलाई द्वारा आमदी नगर हुडको भिलाई नजूल खसरा नं.1/2,2/2 का भाग प्लाट नं. एम.आई.जी. 01/142, रकबा 150 वर्गमीटर भूमि आवेदक के पिता धारक स्वं. आ.स्व.आर.डी.पाण्डेय, आ. केदारनाथ पाण्डेय के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है, धारक की मृत्यु दिनांक 09.08.2007 को हो चुकी है। मृतक धारक के वारिसान उनकी पत्नि श्रीमती कमला देवी पुत्र रामेश्वर प्रसाद, बालेश्वर प्रसाद, आ.स्व.आर.डी. पाण्डेय है। इसके अतिरिक्त अन्य वारिसान नहीं है। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूखण्ड से मृतक धारक का नाम विलोपित कर उनके वारिसानों के नाम पर फौती नामांतरण पश्चात नवीन पट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव एतद् द्वारा सर्व साधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा या आपत्ति हो, तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 06.08.2025 को या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वत: या किसी व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भू-खंड संबंधी जानकारी हो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जावे अथवा कराया जावे। नियत तिथि पश्चात प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15/07/2025 को जारी किया गया।

मुहर

नजूल अधिकारी
दुर्ग

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर जोन क्रमाक 09 मोवा थाना के पीछे स्थित सामुदायिक भवन

क्र/685/न.पा.नि/जोन के 09/2025

रायपुर, दिनांक 15/07/2025

।। प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना ।।

नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 09 में निम्न कार्य हेतु सीलबंद निविदा निम्नानुसार तीन लिफाफा पद्धित से दिनांक 04.08.2025 को संध्या 5.30 तक निविदायें रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से नगर पालिक निगम जोन कार्यालय क्र. 09 में आमंत्रित की जाती है। सि हेतु निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए दिनांक 28/07/2025 को संध्या 5.00 बजे तक आवेदन के साथ निर्धारित राशि जमा कर सकेंगे। दिनांक 30.07.2025 को संध्या 5.00 बजे तक निविदा प्रपत्र जारी होंगे। प्राप्त निविदायें अगले कार्यदिवस को अपरान्ह 12.00 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.	मद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय (रूपये लाख में)	अमानती राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य	निविदा प्रपत्र प्रारूप	समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी	एसओआर दर
1	सामान्य मद	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमाक-51 अतर्गत संकल्प सोसायटी में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य	7.72	8000.00	750.00	A	02 माह	ई रजिस्ट्रेशन द श्रेणी व उससे ऊपर	लोक निर्माण विभाग के भवन एस ओआर दिनाक 01.01.2015 से प्रभावशील तथा निविदा दिनाक तक संशोधित

नोट -

1 कार्य से संबंधित जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन दिवस में नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 09. से प्राप्त की जा सकती है। उक्त निविदा संबंधी जानकारी नगर निगम पोर्टल से भी प्राप्त की जा सकती है।

2 नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ शासन, रायपुर में एकीकृत पंजीयन प्रणाली से सक्षम श्रेणी में पंजीकृत से तीन लिफाफा पद्धति जमा करना है।

3 लिफाफा (अ) में अमानती राशि का एफ.डी.आर. व शपथ पत्र एवं चाही गई समस्त दस्तावेज।

4 लिफाफा (ब) में निविदा प्रपत्र भरकर सीलबंद करना होगा।

5 (अ) + (ब) एक अन्य तीसरे लिफाफे (स) में भरकर ही स्पीड पोस्ट के द्वारा प्राप्त किया जावेगा।

6 सर्वप्रथम लिफाफा (स) खोलने के पश्चात लिफाफा (अ) खोला जावेगा, जिसमें अमानती राशि का एफ.डी. आर. एवं अन्य चाही गई दस्तावेज होने पर ही निविदा प्रपत्र की लिफाफा (ब) खोली जावेगी तथा लिफाफे में 'अ' 'ब' एवं 'स' अंकित होना अनिवार्य है।

7 निविदा में उल्लेखित उपरोक्त दिनांक में शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यालयीन दिवस में कार्यवाही किया जावेगा।

8 सक्षम श्रेणी का ई-रजिस्ट्रेशन, कार्य की राशि का 15 प्रतिशत बैंक साल्वेंशी, अंतिम 03 वर्ष का आई.टी.आर., पेनकार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी. रिटर्न (अंतिम तीन माह), अमानती राशि का एफ.डी. आर. एवं शपथपत्र (रु. 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टांप पेपर के साथ) प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

9 03 वर्ष के आयकर की बाध्यता नये फर्मो के लिए बंधनकारी नहीं होगी। तीन लिफाफा पद्धति में लिफाफा नहीं देने पर निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। ठेकेदारों को फार्म में दिये गये शर्त अनुसार कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

10 किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम, रायपुर के पास सुरक्षित है।

11 ठेकेदारों को फार्म में दिये गये शर्तों के अनुसार कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

12 एस.ओ.आर. दर से 10 प्रतिशत से कम दर प्राप्त होने पर अंतर की राशि पृथक से अमानती राशि एफ.डी.आर. के रुप में इकरारनामा के पूर्व जमा करना होगा।

13 शासकीय अवकाश या आकस्मिक अवकाष्श की स्थिति में तिथि एवं समय में परिवर्तन का अधिकार जोन आयुक्त के पास सुरक्षित होगा।

14 कार्यालय द्वारा निर्धारित नियम व शर्ते प्राक्कलन एवं स्थल का अवलोकन निविदा हेतु आवेदन प्रेषित करने के पूर्व कर लिया जावे जिससे अंतिम समय में कोई विवाद न हो।

15 स्थल विवाद की स्थिति में जोन आयुक्त/आयुक्त महोदय द्वारा कार्यादेश निरस्त किये जाने की स्थिति में किसी प्रकार कर क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगा।

घरों से निकलने वाले गीला और सूखा कचरे को सफाई मित्र (वाहन) को देवें।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक - 09
नगर पालिक निगम, रायपुर

संक्षिप्त-खबर

नगर पंचायत पाटन द्वारा सफ़ाई मित्रों को सुरक्षा सामग्री वितरण किया गया

पाटन (समय दर्शन)। पूरे नगर पंचायत पाटन को स्वच्छ एवं साफरखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नगर पंचायत के सभी सफ़ाई मित्रों को पाटन नगर पंचायत के जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सुरक्षा सामग्री वितरण किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से नगर पंचायत पाटन के सभापति देवेंद्र ठाकुर ,पार्षद संगीता धुरंधर, केशव बंछोर, प्रकाश बिजौरा, सफ़ाई प्रभारी हुकुम देवांगन किशोर वर्मा सहित सभी सफ़ाई कर्मचारी उपस्थित थे।

नवोदय डोंगरगढ़ की रोशनी वर्मा का चयन निवृत्ति गुरूकुल आईएएस कोचिंग के लिए

डोंगरगढ़। नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ ने एक बार फिर उपलब्धि के नए आयाम को छूते हुए गौरव का क्षण प्रदान किया है। विद्यालय की कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा रोशनी वर्मा का चयन प्रतिष्ठित निवृत्ति गुरुकुल उडुपी (कर्नाटक) में हुआ है, जहां वह अगले चार वर्षों तक स्नातक की पढ़ाई के साथ-साथ यूपीएससी परीक्षा की नि:शुल्क कोचिंग प्राप्त करेगी। विद्यालय में नियुक्त निवृत्ति गुरुकुल प्रभारी शिक्षक रामकुमार चंद्रा ने जानकारी दी कि गुरुकुल में चयन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है, जिसमें देशभर के नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों को तीन चरणों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ऐसे में रोशनी वर्मा का चयन विद्यालय के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। प्रभारी शिक्षक श्री चंद्रा ने बताया कि रोशनी वर्मा शुरू से ही एक मेधावी, अनुशासित एवं व्यवहार कुशल छात्रा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी इस सफलता के पीछे सतत परिश्रम, लगन और मार्गदर्शन की अहम भूमिका रही है। विद्यालय के प्राचार्य संजय कुमार मंडल ने छात्रा रोशनी वर्मा को बधाई देते हुए कहा कि यह न सिर्फ विद्यालय बल्कि जिले के लिए भी गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर बच्चों को भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं और अन्य विद्यार्थियों को भी उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निवृत्ति गुरुकुल एक ऐसा संस्थान है जो विशेष रूप से नवोदय विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चयनित कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग उपलब्ध कराता है। चार वर्षों तक विद्यार्थियों को वहां रहने, पढ़ने और यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी के समस्त खर्च का वहन गुरुकुल द्वारा किया जाता है। विद्यालय परिवार ने रोशनी वर्मा की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

फ़र्जी वेतन भुगतान का मामला उजागर, एफआईआर की मांग

राजनांदगांव। पीएमश्री सर्वेश्वरदास नगर पालिक निगम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एक शिक्षक के फ़र्जी नियुक्ति और वेतन भुगतान का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने कलेक्टर और एसपी को लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले की जांच कर एफ़आईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में बताया गया है कि मनोज सोनकलिहारी नामक शिक्षक, जो मूल रूप से धौराभाठा हाई स्कूल में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं, वर्तमान में नियम विरुद्ध तरीके से राजनांदगांव के आत्मानंद स्कूल में पदस्थ हैं। उल्लेखनीय है कि उनकी विधिवत नियुक्ति स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा नहीं की गई है, फिर भी उन्हें डोंगरगांव स्थित आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य पद से वेतन भुगतान किया जा रहा है। श्री पॉल ने बताया कि सभी शिक्षकों को प्रतिदिन जियो टैग एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी होती है, लेकिन मनोज सोनकलिहारी का नाम किसी भी स्कूल की उपस्थिति में नहीं देखा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि उनकी उपस्थिति रिपोर्ट कौन भेज रहा है और वेतन किस आधार पर बन रहा है? क्रिष्टोफर पॉल ने कहा कि उक्त स्कूल का संचालन एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसके पदेन अध्यक्ष स्वयं कलेक्टर होते हैं। ऐसे में समिति की अनुमति और कलेक्टर के अनुमोदन के बिना किसी शिक्षक की नियुक्ति और वेतन भुगतान करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता भी है। उन्होंने मामले में गहराई से जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों से शासन की मंशा और आत्मानंद स्कूलों की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है।

स्कूलों में किताबों और कक्षाओं की कमी, शमसूल आलम ने किया निरीक्षण

राजनांदगांव (समय दर्शन)। अजीत जोगी युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसूल आलम ने सोमवार को शहर के शासकीय स्कूलों का निरीक्षण कर छात्रों की समस्याएं जानी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुआं चौक स्थित शासकीय मिडिल स्कूल और सुंदरा हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मिडिल स्कूल के प्रधानपाठक से जानकारी मिलने पर शमसूल आलम ने बताया कि कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को चार विषयों की किताबें अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, वहीं कक्षा 7वीं के छात्रों को भी कुछ किताबों की कमी से जूझना पड़ रहा है। अध्यापकों ने बताया कि कुछ विषयों की किताबों में बदलाव के चलते वितरण में देरी हो रही है, लेकिन पढ़ाई पुराने सिलेबस से निरंतर कराई जा रही है।

इसके बाद शमसूल आलम ने सुंदरा हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण कर प्राचार्य और विद्यार्थियों से चर्चा की। इस दौरान छात्रों ने बताया कि स्कूल में कक्षाओं की भारी कमी है और एक ही प्रयोगशाला में सभी विषयों के प्रायोगिक कार्य कराए जाते हैं। छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आलम ने इसे भाजपा सरकार और शिक्षा विभाग की विफलता करार दिया।

उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। शाला भवन और संसाधनों की कमी बच्चों की शिक्षा में बड़ी बाधा बन रही है।

शमसूल आलम ने कहा कि अजीत जोगी युवा मोर्चा इन समस्याओं को शासन-प्रशासन के समक्ष उठाएगा और आवश्यक सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष करेगा। उन्होंने छात्रों से संवाद कर उन्हें आश्वस्त किया कि वे उनकी आवाज बनकर आगे लड़ाई लड़ेंगे।

निरीक्षण के दौरान शमसूल आलम के साथ शहर जिलाध्यक्ष बिलाल सोलिन खान, जिला महासचिव ऋषभ रामटेके, नमन पटेल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ की प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीयन धीमा, अंतिम तिथि 29 जुलाई

डोंगरगढ़ (समय दर्शन)। जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ (जिला-राजनांदगांव) में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई तय की गई है। लेकिन जिले सहित मोहला-मानपुर-चौकी और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों में पंजीयन की गति काफी धीमी बनी हुई है।

इस संबंध में विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य संजय कुमार मंडल ने नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय के संयुक्त आयुक्त ज्ञानेन्द्र कुमार ने राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-चौकी और खैरागढ़ जिलों के कलेक्टरों को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर अपने-अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को सक्रिय करने का आग्रह किया है।

प्राचार्य मंडल ने बताया कि राजनांदगांव जिला पूर्व वर्षों में देशभर में पंजीयन के मामले में अग्रणी रहा है, लेकिन इस बार तीनों जिलों में बच्चों का नामांकन अपेक्षानुरूप नहीं हो रहा। इस कारण विद्यार्थियों को मिलने वाले सुनहरे अवसर से वंचित होने का खतरा है।

प्राचार्य मंडल ने दिनांक 16 जुलाई को मोहला ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र देवांगन, मानपुर के बीईओ श्री कोर तथा सहायक बीईओ अरुण मरकाम से मुलाकात की। इन अधिकारियों की पूर्व में नवोदय नामांकन में सक्रिय भूमिका रही है। छुईखदान ब्लॉक के बीआरसी सुजीत सिंह चौहान और दयाल दास बंजारे का भी सहयोग उल्लेखनीय रहा है।

विद्यालय प्रशासन द्वारा बताया गया कि इस प्रवेश परीक्षा को तीनों जिलों के लिए डोंगरगढ़ स्थित नवोदय विद्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा। अभियान के प्रचार-प्रसार में गणित शिक्षक स्नेह अग्रवाल और अनिल कुमार सक्रिय रूप से स्कूलों तक जाकर विद्यार्थियों और पालकों को प्रेरित कर रहे हैं।

प्राचार्य संजय मंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी श्री बघेल से भी भेंट कर पंजीयन की वर्तमान स्थिति की जानकारी साझा की और सभी पांचवीं कक्षा के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करने का निवेदन किया।

विद्यालय प्रशासन ने पालकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का पंजीयन जल्द कराएं, ताकि प्रतियोगी वातावरण में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नवोदय जैसे उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिल सके। पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क और ऑनलाइन है।

मिनी रत्न व्यवस्था गोबर से गई बीती

- राम खिलावन के लिए कौन लड़ेगा नहीं पता

बिलासपुर (समय दर्शन)। राम खिलावन महिलांगे की मौत ये बताती है कि पूंजी पत्तियों के लिए श्रमिक की मौत सड़क पर मरने वाले जानवर से भी हल्की है। रतनपुर हाईवे पर ट्रक चालक ने दर्जन भर से ज्यादा गायों को कुचल कर मार डाला, भाग गया। दैनिक अखबारों ने आधा पेज समर्पित कर दिया। पर एनटीपीसी रलिया राखड डैम में राम खिलावन महिलांगे की मौत खबर लिखने और व्यवस्था की खामियों की तस्वीर छिपाने में हाथ कांपते हैं, मुंह बंद हो जाता है। नियम अनुसार बारिश में राखड़ का ट्रांसपोर्टिंग नहीं होता पर एनटीपीसी में चल रहा है। नियमों को ताक पर रखकर, सुरक्षा व्यवस्था को ढीला छोड़कर, फिर कुछ लोगों के लाभ के लिए डेम पर 14 तारीख रात 11:00 की घटना है। डंपर में राखड़ भरा जाना था। राम खिलावन के साथ कोई हेल्पर नहीं था। जबकि होना चाहिए। वह डाले पर त्रिपाल लेने उतरा और उसी समय मशीन से राखड़ भरा जाने लगा। मौत हो गई, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई की मस्तूरी थाना क्षेत्र में सब कुछ पता होने के बावजूद 15 तारीख की दिनभर व्यवस्था ने जिसमें एनटीपीसी, ठेका कंपनी और पुलिस तीनों शामिल है। चुप्पी साध ली रात को मृत देह निकाल ली गई सब कुछ आम नागरिकों से छुपा कर किया जा रहा था। बारिश में राखड डैम में पशु मरते हैं और कभी-कभी इस तरीके से इंसान भी मर जाते हैं।

बसना में सेंट्रल हाल लाइब्रेरी की सौगात

- डॉ. सम्पत अग्रवाल की अनुशंसा पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बसना मे सेन्ट्रल हाल निर्माण के लिए दी 441:49 लाख रूपये की स्वीकृति

रायपुर (समय दर्शन)। बसना विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए एक महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति मिली है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बसना विधानसभा क्षेत्र में बसना विधायक डॉ संपत अग्रवाल की अनुशंसा पर एक अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण के लिए 441.49 लाख रुपये (लगभग 4.41 करोड़ रुपये) की बड़ी राशि स्वीकृत की है। इस जनहितैषी निर्णय के लिए बसना के लोकप्रिय विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव का हृदय से आभार व्यक्त किया है।

बसना के लिए ऐतिहासिक सौगातः ज्ञान का नया केंद्र : विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उन्हें एक पत्र के माध्यम से इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति से अवगत कराया है। विधायक डॉ. अग्रवाल ने इस सौगात को बसना और पूरे क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक बड़ा वरदान बताया। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति बसना विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास और यहां की जनता की वर्षों पुरानी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदान की गई है।

विधायक डॉ. अग्रवाल ने विस्तार से बताया कि स्वीकृत राशि से नगर पंचायत बसना में 250 सीटों की क्षमता वाला एक भव्य सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह परियोजना शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में मील का पत्थर साबित होगी। हमारे छात्र, शोधकर्ता और आम जनता को अब गुणवत्तापूर्ण अध्ययन और पठन-पाठन का बेहतरीन वातावरण मिलेगा, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल होगा।

पारदर्शिता और जनभागीदारी: विकास में सबका साथ : उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने पत्र में विधायक डॉ. संपत अग्रवाल से अनुरोध किया है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य को अपने मार्गदर्शन में शीघ्रता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं. साथ ही, संबंधित अधिकारियों को भी इस परियोजना की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए कहा कि इस कार्य को अधिकतम प्रभावी रूप से पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि विभाग द्वारा स्वीकृत इन कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए, ताकि वे सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी कर सकें।

विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने दृढ़ता से कहा कि इन परियोजनाओं की प्रगति और उनसे होने वाले लाभों की जानकारी आम जनता तक व्यापक रूप से पहुंचाई जाएगी। यह न केवल पारदर्शिता को बढ़ाएगा, बल्कि जनता का विश्वास और सहयोग भी सुनिश्चित करेगा, जो किसी भी विकास कार्य की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

विधायक ने जताया आभार, क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई : विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने इस ऐतिहासिक स्वीकृति पर अपनी असीम प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह कदम निश्चित रूप से बसना विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. मैं प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री अरुण साव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बसना की जनता की जरूरतों को समझते हुए यह महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान की।

यह परियोजना बसना में शैक्षिक क्रांति लाने और युवाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को एक नई दिशा मिलेगी. विधायक डॉ. अग्रवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है।

थाना प्रभारी को दिया जबर हरेली रेली भेलई का नेवता

होमन सिंह ठाकुर समय दर्शन नंदिनी अहिवारा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने नव नियुक्त नंदिनी नगर थाना प्रभारी पारस ठाकुर जी को भिलाई में होने वाले प्रदेश स्तरीय जबर हरेली रेली का न्योता दिया और समस्त स्टाफके साथ आने का आग्रह किया। प्रकृति देवता और कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों को धन्यवाद देने ,छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बचाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है जिसका ये लगातार आठवां साल है। इस बड़े आयोजन में पुरे छत्तीसगढ़ से हजारो की शंखया में लोग यहां हरेली मनाने आते हैं। रेली में विभिन्न प्रकार के चलित छत्तीसगढ़िया सांस्कृतिक कार्य क्रम और झाँकी रहती है साथ ही विभिन्न प्रकार के समाज सेवी संगठन के द्वारा जल पान की व्यवस्था रहती। रेली समापन के पस्चात अंत में छत्तीसगढ़िया सांस्कृतिक मंचीय कार्यक्रम होता है । नेवता जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी (जिला उपाध्यक्ष) कौशल साहू,परमेश्वर ठाकुर (संरक्षक) छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अहिवारा नगर ,गोवर्धन ताम्रकार (संयोजक)छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अहिवारा नगर,बसंत साहू (उपाध्यक्ष) छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अहिवारा नगर,होमन सिंह ठाकुर के द्वारा दिया गया।

हरेली बर्ड काउंट : शोधार्थियों और छात्रों ने पक्षियों की गणना कर जाना उनका व्यवहार...पाटन के टोलाघाट में बर्ड वॉक का हुआ आयोजन

बलराम यादव

पाटन। बर्ड काउंट इंडिया की ओर से हरेली बर्ड काउंट का आयोजन किया गया।पाटन के टोलाघाट में बर्ड वॉक में महात्मा गांधी वानिकी विश्वविद्यालय के शोधार्थी और छात्र छात्राएं शामिल हुए।टोलाघाट में मंदिर के पीछे पेड़ों में बने घोसलों मे विद्यार्थियों ने बर्ड वॉच किया।

पक्षी विशेषज्ञ राजू वर्मा के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने पक्षी दर्शन कर उनकी गणना की साथ ही घोसलों में पक्षियों के व्यवहार को करीब से जाना ।इस दौरान टोलाघाट में 33 प्रजाति की लगभग 400 पक्षियों की गणना की गई।

इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। शोधार्थियों और छात्रों ने दूरबीन और अलग-अलग कैमरों से ओपन बिल करमोरेंट नाईट हेरॉन बगुला बया मीडियम इग्रेट आदि पक्षियों के घोंसले देखे।

घोसलों की सुरक्षा अंडो की सुरक्षा और अभी अभी अंडे से बाहर निकले चूजों को देखना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही रोमाचक रहा।

विद्यार्थियों ने सामान्य पक्षी जैसे परपल रमप्ड सनबर्ड, ब्रॉन्ज विंग्ड जकाना, लैपविंग जैसे कई पक्षियों की तस्वीर लोगों ने अपने मोबाइल से क्लिक की।

बर्ड काउंट के विषय मे श्री वर्मा ने बताया कि पक्षियों की गणना से यह पता चल सकता है कि कुछ प्रजातियां एक विशेष क्षेत्र में क्यों एकत्रित हो रही हैं, या वे एक विशेष क्षेत्र से क्यों पलायन कर रही हैं। यह जानकारी पक्षियों के आवासों की रक्षा करने और उनके संरक्षण के प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जा सकती है।

यह कार्यक्रम Bird Count India द्वारा आयोजित किया गया ।छत्तीसगढ़ में हरेली बर्ड काउंट का आयोजन 13 से 16 जुलाई 2025 तक छत्तीसगढ़ में किया गया । इस आयोजन का उद्देश्य हरेली त्योहार के दौरान पक्षियों की विविधता का दस्तावेजीकरण करना था।

बर्ड वाक में नेचर वेलफेयर के अभिषेक मैत्री सहित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के पीएचडी स्कोलर और विद्यार्थी दुष्यंत साहू खिलेश टेकाम हिमांशु साकेत कोसमा

संध्या रोशनी प्रधान राजेश्वरी नाग सौरभ शिवम कोमल गीतांजलि ओमप्रकाश भावेश वेदप्रकाश उपस्थित रहे।

स्वामित्वधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक रोहित खड़तकर द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स ग्राम छाटा, पोस्ट देवादा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.), पिन-491111 से मुद्रित कर 65/1920, परशुराम नगर प्रोफेसर कालोनी, रायपुर (छ.ग.) पिन- 492001 से प्रकाशित। संपादक :- दामोदर राव, फोन नं.-0771-4218364, मो. 9303404360, ईमेल- samaydarshanraipur@gmail.com, RNI: CHHHIN/2018/76878, डाक पंजीयन /रायपुर संभाग/63/2025-27